website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक
रॉयल पत्रिका

वर्ष :13 | अंक : 276 | पेज: 8 | जयपुर, शनिवार 13 सितम्बर 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 से 15 सितम्बर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी मिज़ोरम जाएंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यहां वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है।

मिजोरम में पीएम मोदी

कल शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम के आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी।

मणिपुर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 12:30 बजे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इन्फोटेक विकास (MIND) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावास आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी दोपहर लगभग 2:30 बजे इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे।

असम में पीएम मोदी

इम्फाल के बाद पीएम मोदी असम का दौरा करेंगे और शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

वहीं, 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह सुबह करीब 11 बजे दरांग में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद, पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:45 बजे गोलाघाट में असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वह गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल और बिहार रहेंगे

15 सितंबर को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 9:30 बजे कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वह पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशनों को लगभग 500 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष भी वितरित करेंगे तथा कुछ सीएलएफ अध्यक्षों को चेक सौंपेंगे।

नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की संभालेगी अंतरिम प्रधानमंत्री का पद

नेपाल (एजेंसी)। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। यह कदम प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उठाया गया है, जिन्होंने युवाओं के नेतृत्व में चल रहे

बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ा। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 8:45 बजे स्थानीय समय पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित होगा। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने जुलाई 2016 से जून 2017 तक इस पद पर काम किया। वे अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं। उनका वकालत का सफर 1979 में शुरू हुआ, 2007 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और 2009 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुईं। देश में चल रहे जेन-जेड आंदोलन के नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कार्की निष्पक्ष और विश्वसनीय हैं, इसलिए वे इस कठिन समय में सही विकल्प साबित होंगी।

इसी बीच नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। यह कदम उन प्रदर्शनों की प्रमुख मांगों में से एक था, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ भड़क उठे थे। हालांकि, कई राजनीतिक दलों और सिविल सोसायटी समूहों ने संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन की अपील की है। वहीं आज प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा के सभापति ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने प्रदर्शनों में हुई मौतों पर संवेदना जताई और घायलों के लिए चिकित्सकीय सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने हिंसा और आगजनी की घटनाओं की निंदा की, जिनमें बनश्वोर, सिंहदरबार और अन्य इलाकों में सरकारी कार्यालयों, मीडिया हाउस, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ऐतिहासिक अभिलेखों को नुकसान पहुंचा।

संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति देश की संप्रभुता, नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और क़ानून के शासन को बनाए रखते हुए संवैधानिक समाधान खोजने के प्रयास कर रही हैं।

शपथ ग्रहण के बाद सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति का संभाला कार्यभार

नई दिल्ली(एजेंसी)। सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभाला। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली है, जिन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था।

उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया और इस अवसर की तस्वीरें भी साझा कीं। शपथ ग्रहण से पहले सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सत्य व अहिंसा के आदर्शों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने सदैव अटल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित स्मारक पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। किसान घाट पर जाकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन किया। संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने वहां एक पौधा भी लगाया। उन्होंने इस दौरान देश की समृद्ध विरासत और सतत भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों से की मुलाकात

-मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ईयू के कृषि और खाद्य आयुक्त क्रिस्टोफ हेन्सन, व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बैठक का मकसद भारत-ईयू के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द पूरा करना है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "भारत एक संतुलित और परस्पर लाभकारी एफटीए के लिए प्रतिबद्ध है, जो व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोलेगा और भारत एवं यूरोप दोनों की साझा प्रगति को मजबूत करेगा।" उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर यह भी बताया कि भारत-ईयू एफटीए की 13वें दौर की बातचीत जारी है और दोनों पक्ष इसके जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक के दौरान भारत ने जोर दिया कि व्यापार वार्ता में केवल टैरिफ ही नहीं बल्कि गैर-टैरिफ बाधाओं (NTBs) पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि नियामक ढांचे समावेशी और संतुलित होने चाहिए, ताकि वे व्यापार में रुकावट न बनें। अब तक दोनों पक्ष 11 अध्यायों को अंतिम रूप दे चुके हैं, जिनमें कस्टम्स, व्यापार सुविधा, डिजिटल ट्रेड और पूंजी प्रवाह जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, रूल्स ऑफ ओरिजिन, मार्केट एक्सेस और वाइन व डेयरी जैसे उत्पादों पर टैरिफ को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं।

गौरतलब है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2023-24 में दोनों के बीच व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंचा। एफटीए पर 13वां दौर की बातचीत इस हफ्ते नई दिल्ली में होगी और अगला दौर ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रस्तावित एफटीए से ऑटो उद्योग को विशेष लाभ होगा। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि ऑटो उद्योग हमारे प्रस्तावित प्रावधानों को आकर्षक पाएगा, जिससे व्यवसाय बढ़ेंगे, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी होगी, नवाचार और शोध को बढ़ावा मिलेगा और भारत में उत्पादन विकसित होगा।" इस बीच, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज शुक्रवार को यूरोपीय संघ की राजनीतिक और सुरक्षा समिति (PSC) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चेयर डेलफिन प्रोंक ने किया, जो पहली बार एशिया दौरे पर आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को गहरा करने और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय हालात पर विचार-विमर्श हुआ।

चार दिन बाद खुला भारत-नेपाल का सोनौली बॉर्डर

-आवश्यक सामान से भरे ट्रकों को मिली अनुमति

नेपाल (एजेंसी)। नेपाल में जारी अशांति और जेन जेड (Gen Z) विरोध प्रदर्शनों के कारण पिछले चार दिन से बंद पड़ा भारत-नेपाल का सोनौली बॉर्डर आज शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया। इसके बाद जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई।

बॉर्डर बंद रहने से सैकड़ों ट्रक भारतीय सीमा पर फंसे हुए थे, जिनमें प्याज, नारियल और कच्चा माल जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान थे। तमिलनाडु से नारियल लेकर काठमांडू जा रहे ट्रक चालक विष्णु ने बताया कि वे चार दिन तक बॉर्डर पर फंसे रहे। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि काठमांडू तक सब ठीक रहेगा। थोड़ा डर जरूर है, लेकिन यहां भोजन और पानी की सुविधा मिली।"

वहीं नेपाल में ईंधन संकट भी गहराता जा रहा है। इस कारण वहां से ट्रक भारत आकर पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। एक नेपाली चालक ने कहा, "नेपाल में कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं है। सरकार ने हमें भारत भेजा है ताकि हम ईंधन खरीद सकें।"

नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शन सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और

राजनीतिक अस्थिरता व भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए थे।

इसी दौरान नेपाल की अलग-अलग जेलों से फरार 67 कैदियों को भारत में घुसने की कोशिश करते हुए भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने पकड़ लिया, इनमें एक महिला भी शामिल है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, काठमांडू घाटी में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में मरने वालों की संख्या 34 तक पहुंच गई है, जबकि पूरे देश में अब तक 1,368 लोग घायल हुए।

यूपी के खुर्जा में 'अनोखी दुनिया' पार्क का शुभारंभ

-सिरेमिक वेस्ट से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन

यूपी (एजेंसी)। वेस्ट से आर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में

'अनोखी दुनिया' नामक पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अनोखे पार्क में खासतौर पर सिरेमिक वेस्ट से बनी विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि 'वेस्ट टू वंडर' थीम पर आधारित कला को नई पहचान भी देती है।

जब टाइल्स, ईंट, बर्तन, सजावटी सामान और सैनिटरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उनका एक बड़ा हिस्सा टूट-फूट, खराब क्वालिटी या अधूरा होने के कारण फेंक दिया जाता है। यही सिरेमिक वेस्ट कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से टूटी हुई टाइलें, अधूरी या खराब बनी सिरेमिक वस्तुएं, उत्पादन के दौरान निकला स्क्रैप और पाउडर शामिल होते हैं। इन वेस्ट को अब रिसाइकल करके पार्क, सड़क, सजावटी सामान और आर्टवर्क बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण (बीकेडीए) के उपाध्यक्ष डॉ. अंकुर लाठर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, "खुर्जा ने विश्व स्तर पर अपने बेहतरीन सिरेमिक उत्पादों के लिए पहचान बनाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पार्क तैयार किया गया है, जहां सिरेमिक वेस्ट को शानदार कलाकृतियों में बदला गया है।"

इसी बीच केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक 'विशेष अभियान 5.0' की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के तहत उत्पन्न ई-वेस्ट का निपटान करना, स्पेस मैनेजमेंट और फील्ड ऑफिसों में कार्यस्थल अनुभव को बेहतर बनाना है। इससे पहले 2 अक्टूबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक चले 'विशेष अभियान 4.0' ने स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को लेकर एक ऊंचा मानक स्थापित किया था।

इस अभियान में कोयला मंत्रालय (MoC) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। डीएआरपीजी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने स्पेस फ्रीड कैटेगरी में पहला स्थान और राजस्व अर्जित करने में चौथा स्थान हासिल किया। मंत्रालय ने 100% जनता की शिकायतों और पीएमओ रेफरेंस का निपटान किया। इसके अलावा 71,632 फाइलों की समीक्षा और 69,227 फाइलों को हटाया गया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया का भी व्यापक इस्तेमाल किया और 2,163 ट्वीट, 1,137 प्रेस विज्ञप्तियां और 61 पीआईबी बयान जारी किए, जिससे अभियान की उपलब्धियां और पहलों को व्यापक स्तर पर उजागर किया गया।

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी

-भूस्खलन के बाद दो हफ्ते तक रही स्थगित

नई दिल्ली (एजेंसी)। भूस्खलन के कारण दो हफ्ते से अधिक समय से स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार से फिर से शुरू होने वाली है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार को यह घोषणा की। बोर्ड ने कहा है कि वैष्णो देवी यात्रा की बहाली सशर्त है और अनुकूल मौसम की स्थिति पर निर्भर है।

जानकारी और बुकिंग के लिए वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी। जानकारी और बुकिंग के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।"

पिछले महीने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी

गौरतलब हो, जम्मू संभाग में 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन होने से 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 10 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इसके कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। कटरा में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया था।

वहीं, भूस्खलन त्रासदी के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) की आलोचना हुई, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी यात्रा के मामलों का प्रबंधन करने वाले एसएमवीडीएसबी के अधिकारियों को दोषी ठहराया। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर अखदुवारी के पास हुए भूस्खलन की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को शामिल किया गया। उपराज्यपाल के आदेश में कहा गया था, "यह समिति अगले सप्ताह में श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी।" रियासी जिले के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में हर साल करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं।

नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों से डरे प्रवासी, हालात बेहद खराब

नेपाल (एजेंसी)। नेपाल में जनरेशन जेड के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश के हालात को

बदलकर रख दिया है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के खिलाफ छिड़े इस विरोध प्रदर्शन के कारण कई लोगों को जान गवानी पड़ी है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। नेपाल के हालात को लेकर महाराष्ट्र के नालासोपारा में रहने वाले नेपाली प्रवासियों ने चिंता जाहिर की। नालासोपारा में रहने वाला एक नेपाली परिवार अपने देश की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। परिवार की सदस्य कमला गौतम ने न्यूज़ एजेंसी से खास बातचीत में नेपाल के हालात और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। कमला गौतम ने बताया, "मैं नालासोपारा में रहती हूं, लेकिन मेरा पूरा परिवार नेपाल में है। हाल ही में नेपाल के कई इलाकों जैसे बेनी, काठमांडू और पोखरा घाटी में काफी क्षति हुई है। माहौल बहुत खराब है। मम्मी-पापा और रिश्तेदारों के लगातार फोन आ रहे हैं। सब डरे हुए हैं। मैं वहां जाना चाहती हूं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जा नहीं सकती।" कमला के मुताबिक, नेपाल की मौजूदा स्थिति ने प्रवासी नेपाली समुदाय को भी बेचैन कर दिया है। वहां हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं और परिवार की सलामती को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।

बता दें कि नेपाल में जेन-जी के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेकर कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच देश की स्थिति संभालने के लिए नेपाली सेना सामने आई और जल्द से जल्द हालात काबू करने के दावों के साथ ही अंतरिम सरकार के गठन का भरोसा दिया। सेना जेन-जी का समर्थन तो करती है, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे सैन्य तख्तापलट में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह जल्द से जल्द समाधान चाहती है ताकि कानून-व्यवस्था बहाल हो सके। नेपाली सेना के पास फिलहाल इतनी शक्ति है कि वह राजनीतिक दलों को एक समझौते पर पहुंचने और अंतरिम प्रमुख के रूप में एक उपयुक्त उम्मीदवार खोजने के लिए मजबूर कर सके।

राज्यपाल बागडे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शुक्रवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के नेतृत्व में भारत संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में और अधिक सशक्त होगा।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

संसदीय गरिमा को और मजबूती मिलने की उम्मीद

संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में उपराष्ट्रपति का पद बेहद अहम माना जाता है। यह पद न सिर्फ संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है, बल्कि राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारु और गरिमामय ढंग से संचालित करने का दायित्व भी इसी पद पर आसीन व्यक्ति के कंधों पर होता है। हाल ही में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित किया तो यह कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और पार्टी संगठन में उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सादगीपूर्ण जीवनशैली से अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर राजनीति में "सरप्राइज फैक्टर" की रणनीति सामने रख दी। यह चुनाव महज संख्याबल का खेल भर नहीं था। आंकड़ों के लिहाज से राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों का बहुमत साफ था। फिर भी इस चुनाव में दिलचस्पी इसलिए रही क्योंकि बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल जैसे दलों ने मतदान से दूरी बनाकर रखा, जिससे जीत का अंतर राजनीतिक दृष्टि से एक अहम संदेश बन गया। राधाकृष्णन की जीत ने न सिर्फ राजग की मजबूती को दिखाया, बल्कि इस बात को भी रेखांकित किया कि भाजपा अपने संगठनात्मक निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ऊंचे संवैधानिक पदों पर भी आगे बढ़ा सकती है। राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से भी महत्व रखता है। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में भाजपा को लंबे समय से सीमित राजनीतिक सफलता मिलती रही है। ऐसे में वहां से किसी वरिष्ठ नेता को इस तरह के पद पर पहुंचाना भाजपा के लिए दूरगामी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। यह कदम कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने वाला है कि पार्टी क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक निष्ठा दोनों को महत्व देती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह भी गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का पद केवल औपचारिकता भर नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अक्सर तीखी बहसें होती हैं। ऐसे में सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति की भूमिका बहुत संवेदनशील और निष्पक्ष होनी चाहिए। सीपी राधाकृष्णन की छवि कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार राजनेता की रही है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि वे इस भूमिका को पूरी गरिमा के साथ निभाएंगे। उनकी सादगी और सहज स्वभाव उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं, जो संवाद और सहमति के रास्ते को प्राथमिकता दे सकता है। यह चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस परंपरा को भी मजबूत करता है जिसमें बड़े संवैधानिक पदों पर उन लोगों को जगह मिलती है, जो राजनीतिक रूप से जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं। राधाकृष्णन जैसे नेता का उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने वाला है।

ट्रम्प की अस्थिर नीतियाँ और विरोधाभासी बयान अमेरिका को अविश्वसनीय बना रहे हैं

-भारत के लिए अब संतुलित, बहुध्रुवीय और आत्मनिर्भर कूटनीति ही सुरक्षित राह

दुनिया की राजनीति आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ एक गलत बयान, एक अचानक पलटा हुआ रुख या किसी महाशक्ति की अस्थिर नीति पूरे वैश्विक समीकरण को बदल देती है। अमेरिका, जो कभी लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थिर कूटनीति का प्रतीक माना जाता था, डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में भरोसे की इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा। ट्रम्प के बयानों, फैसलों और अचानक बदले रवैये ने यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की नीतियाँ किसी स्थिरता पर नहीं, बल्कि क्षणिक लाभ और व्यक्तिगत राजनीतिक हितों पर टिकी हुई हैं। हाल ही में ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "वेरी गुड फ्रेंड" बताया और उनसे संवाद की इच्छा जताई। पर उसी समय उन्होंने यूरोपीय संघ से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की भी बात कही। यह परस्पर विरोधाभासी रवैया केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अमेरिका अब सच में भरोसे के काबिल बचा है?

ट्रम्प की कूटनीति: एक अस्थिर परिपाटी

ट्रम्प के नेतृत्व वाली अमेरिकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनिश्चितता है। कभी वे किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, तो कभी अचानक उसे अपनी आर्थिक विफलताओं या राजनीतिक संकटों का कारण ठहराने लगते हैं। भारत के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और रूस-भारत-चीन समीकरण को मजबूत किया, तो ट्रम्प बेचैन दिखे। वे यह समझते हैं कि अमेरिका की "सुपरपावर" वाली छवि को यह नया ध्रुव चुनौती दे रहा है।

उदाहरण

ईरान परमाणु समझौता: पहले समर्थन और फिर अचानक समझौते से बाहर निकल जाना। पेरिस क्लाइमेट डील: जलवायु परिवर्तन पर विश्व-व्यापी सहमति से ट्रम्प का हट जाना। नाटो (NATO) सहयोगियों पर बयान: जर्मनी और फ्रांस जैसे सहयोगियों को भी अपमानित करना। भारत के प्रति रुख: कभी भारत को "सुपर डेमोक्रेसी" कहते हैं, तो कभी "जॉब्स चुराने वाला देश" बता देते हैं। यह अनिश्चितता ही ट्रम्प कूटनीति का आधार बन चुकी है।

भारत-अमेरिका संबंध: भरोसे की दरारें

भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दो दशकों में काफी मजबूत हुए थे। आईटी, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में दोनों देशों ने एक-दूसरे को रणनीतिक सहयोगी माना। लेकिन ट्रम्प के नेतृत्व में यह रिश्ते खटास से गुजर रहे हैं। ट्रेड टैरिफ: अमेरिका बार-बार भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देता है। वीज़ा पॉलिसी: एच-1बी वीज़ा पर रोक लगाकर भारतीय पेशेवरों को निशाना बनाना। रूस-यूक्रेन युद्ध: भारत के तटस्थ रुख पर अमेरिका का असंतोष। रक्षा समझौते: कई बार ट्रम्प ने कहा कि भारत रक्षा के नाम पर अमेरिका का "फ्री राइडर" है। मोदी का यह कहना कि भारत और अमेरिका "प्राकृतिक सहयोगी" हैं, अब केवल औपचारिकता लगने लगी है।

ईयू बनाम अमेरिका: नया वैश्विक समीकरण

ट्रम्प की नीतियों ने यूरोपीय संघ को भी अमेरिका से दूर कर दिया। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क जैसे देश अब खुले तौर पर अमेरिका की नीतियों का विरोध करने लगे हैं। ट्रम्प की "अमेरिका फर्स्ट" नीति ने "ग्लोबल कोऑपरेशन" को कमजोर किया। रूस-यूक्रेन युद्ध में यूरोप ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की बात की है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। भारत-ईयू ट्रेड संबंध अधिक लचीले और भरोसेमंद दिखाई देने लगे हैं, जबकि अमेरिका अविश्वसनीय।

रूस-चीन-भारत ध्रुव: ट्रम्प की बेचैनी

आज दुनिया बहुध्रुवीय (multi-polar) होती जा रही है। रूस: भारत को सस्ता तेल और हथियार उपलब्ध करा रहा है। चीन: भले ही भारत-चीन सीमा विवाद है, लेकिन आर्थिक स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापार मजबूती से जारी है। भारत: वैश्विक दक्षिण (Global South) का नेतृत्व करने की कोशिश में है। ट्रम्प को लगता है कि यह ध्रुव अमेरिका की "सुपरपावर" वाली छवि को सीधी चुनौती दे रहा है। यही वजह है कि वे भारत को कभी दोस्त, कभी दुश्मन बताकर अस्थिर माहौल बनाते रहते हैं।

भारत की कूटनीतिक चुनौती

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह किसी एक महाशक्ति पर भरोसा न करे। यदि भारत ट्रम्प की "दोस्ती" पर अत्यधिक निर्भर हो जाएगा, तो अगले ही दिन अमेरिका भारत को रूस का फाइनेंसर और चीन का साथी बताकर कठोर कदम उठा सकता है। भारत को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी—जहाँ अमेरिका, रूस, ईयू और एशियाई साझेदार सबके साथ रिश्ते कायम रहें। भारत की विदेश नीति "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) पर आधारित है। यही नीति उसे ट्रम्प जैसे अविश्वसनीय नेतृत्व से बचाती है।

ट्रम्प और विकासशील देश

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी ट्रम्प का रवैया चिंता का विषय है। लैटिन अमेरिका में उन्होंने मेक्सिको और ब्राज़ील को निशाना

बनाया। एशिया में पाकिस्तान और तुर्की पर कठोर बयान दिए। अफ्रीका को "shithole countries" कहकर अपमानित किया। इससे स्पष्ट है कि ट्रम्प का नेतृत्व सहयोग और विश्वास पर नहीं, बल्कि दबाव और अपमान पर टिका है।

आर्थिक अस्थिरता और ट्रम्प

ट्रम्प अपने घरेलू आर्थिक संकटों को छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर बयानबाज़ी करते हैं। अमेरिका में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है। डॉलर की वर्चस्वता पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। चीन और रूस डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ट्रम्प भारत या किसी और देश को बलि का बकरा बनाने से पीछे नहीं हटते।

भारत की राह: परिपक्व कूटनीति

भारत को समझना होगा कि अमेरिकी भरोसा स्थायी नहीं है। इसलिए— ऊर्जा सहयोग: रूस, खाड़ी देशों और अफ्रीका से संतुलित आपूर्ति। रक्षा क्षेत्र: अमेरिका पर निर्भरता घटाकर यूरोप, रूस और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना। ट्रेड रिलेशन: ईयू, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी। बहुपक्षीय मंच: BRICS, SCO और G20 में सक्रिय भागीदारी। भारत की यही परिपक्व कूटनीति ट्रम्प जैसे अस्थिर नेतृत्व के सामने ढाल का काम करेगी। डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति ने दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि अमेरिका अब वैसा भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहा जैसा कभी माना जाता था। आज जब भारत वैश्विक मंच पर एक बड़ी ताक़त बन रहा है, तब उसे अमेरिका की "दोस्ती" के दिखावे से ज़्यादा अपनी स्वतंत्र कूटनीतिक राह पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा इस बात का नहीं है कि ट्रम्प कल भारत को क्या कहेंगे, बल्कि इस बात का होना चाहिए कि भारत अपनी नीतियाँ कितनी संतुलित और दूरदर्शी रखता है। यही रणनीति भारत को "ट्रम्प के नेतृत्व वाले अविश्वसनीय अमेरिका" से आगे बढ़कर सशक्त और स्वतंत्र वैश्विक शक्ति बनाएगी।

भविष्य की कूटनीति: भारत के लिए सबक

भारत के सामने आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सबक यही है कि वह किसी भी एक देश, खासकर अमेरिका, पर अपनी विदेश नीति या आर्थिक रणनीति आधारित न करे। आज दुनिया "डिकपलिंग" और "फ्रेंडशोरिंग" जैसे नए व्यापारिक समीकरणों से गुजर रही है। अमेरिका बार-बार भारत को "प्राकृतिक साझेदार" कहकर अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन उसी वक्त वह यूरोपीय संघ को भारत पर टैरिफ लगाने की सलाह देता है। भारत को यह समझना होगा कि ट्रम्प के नेतृत्व वाला अमेरिका केवल "तत्कालिक लाभ" और "घरेलू राजनीति" को ध्यान में रखकर फैसले करता है। उनकी प्राथमिकता अमेरिका की आंतरिक राजनीति होती है, चाहे उसके लिए वैश्विक रिश्तों का नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। यही कारण है कि भारत की नीति अब बहुध्रुवीय होनी चाहिए। उसे यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ साझेदारी गहरी करनी होगी। यदि भारत केवल ट्रम्प या अमेरिका पर भरोसा करेगा, तो यह कूटनीतिक अपरिपक्वता साबित होगी।

नेपाल में जेन-जी आंदोलन: दीर्घकालीन समाधान तो केवल राजनीतिक संवाद से ही निकलेगा

-भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और असंतोष: क्यों सड़कों पर उतरी नेपाल की युवा पीढ़ी

नेपाल इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर लोकतंत्र की नींव हिलती हुई प्रतीत हो रही है, दूसरी ओर नई पीढ़ी यानी जेन-जी (Gen-Z) का गुस्सा सड़कों पर उफान पर है। यह आंदोलन महज़ क्षणिक भावनाओं का विस्फोट नहीं है, बल्कि गहरे असंतोष और बदलाव की तीव्र मांग का प्रतीक है। जिस तरह राजधानी काठमांडू और अन्य हिस्सों में युवा भीड़ ने पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है, उसने नेपाल की सत्ता संरचना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जड़ों को हिला दिया है। इस पूरे संकट की सबसे अहम बात यह है कि इसे केवल बल प्रयोग से नहीं सुलझाया जा सकता। सेना की तैनाती और पुलिस बल का इस्तेमाल शायद तत्कालिक रूप से हालात को नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन दीर्घकालीन स्थिरता केवल राजनीतिक संवाद, सुधार और जनता की वास्तविक मांगों को समझने से ही आ सकती है।

जेन-जी आंदोलन की पृष्ठभूमि

नेपाल ने पिछले दो दशकों में अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। राजतंत्र से लोकतंत्र, गृहयुद्ध से शांति समझौता और फिर संघीय गणराज्य तक की यात्रा आसान नहीं रही। इन सबके बीच आम जनता, खासकर युवाओं की अपेक्षाएँ लगातार बढ़ती गईं। आर्थिक मोर्चा: बेरोज़गारी, पलायन और आर्थिक अवसरों की कमी सबसे बड़ी समस्या रही है। लाखों नेपाली युवा रोज़गार के लिए खाड़ी देशों, मलेशिया और भारत की ओर पलायन कर गए। भ्रष्टाचार और राजनीति से मोहभंग: लगातार बदलती सरकारें और नेताओं का भ्रष्टाचार युवाओं के लिए सबसे बड़ी निराशा का कारण बना। डिजिटल पीढ़ी की जागरूकता: इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए जेन-जी पीढ़ी वैश्विक घटनाओं से जुड़ी। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल आज़ादी को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। इन्हीं परिस्थितियों में यह आंदोलन जन्मा। यह केवल "विरोध" नहीं है, बल्कि "सकारात्मक बदलाव" की चाह का प्रतीक है।

आंदोलन की मौजूदा स्थिति

काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा पारंपरिक नेताओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी राजनीतिक जमातें जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रही हैं। संसद भंग करने और अंतरिम सरकार की मांग उठ रही है। आंदोलन बगैर किसी स्थापित नेतृत्व के चल रहा है, जिससे सरकार के लिए संवाद के प्रतिनिधि ढूँढना कठिन हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आंदोलन के मुख्य हथियार बने हैं, जहां से नारे, वीडियो और अपीलें वायरल होती हैं। सेना की तैनाती ने हालात को नियंत्रण से बाहर जाने से रोका, लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति नहीं टिक सकती। लोकतंत्र में समाधान हमेशा बातचीत से निकलता है, न कि हथियारों से।

जड़ें घरेलू असंतोष में, न कि षड्यंत्र में

कई राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई "गुप्त ताक़तें" काम कर रही हैं। पड़ोसी देशों या वैश्विक शक्तियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु असली वजह घरेलू असंतोष ही है।

जनता की लंबे समय से उपेक्षित मांगें

भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद
आर्थिक अवसरों की कमी
सरकारी संस्थाओं पर अविश्वास
यही वो बुनियादी कारण हैं जिनसे यह आंदोलन भड़का।

पड़ोसी देशों की नज़र

नेपाल का भू-राजनीतिक महत्व हमेशा से बड़ा रहा है। भारत और चीन दोनों इस संकट पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। भारत: उसकी प्राथमिकता नेपाल में स्थिरता बनाए रखना है। अस्थिर नेपाल भारत की सुरक्षा और सीमाई इलाकों के लिए ख़तरा बन सकता है। चीन: वह

भी नेपाल में राजनीतिक स्थिरता चाहता है ताकि अपनी आर्थिक और सामरिक परियोजनाएँ सुचारु रूप से चलती रहें। दोनों शक्तियाँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बच रही हैं और केवल स्थिरता की वकालत कर रही हैं।

संभावित ख़तरा: बांग्लादेश जैसी अस्थिरता

यदि काठमांडू जल्द ही आंतरिक घावों को नहीं भरेगा, तो नेपाल बांग्लादेश जैसी अस्थिरता की राह पर फिसल सकता है। सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अराजकता से निवेशकों का भरोसा उठ जाएगा। पर्यटन, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बुरी तरह प्रभावित होगा। युवा वर्ग और अधिक निराश होकर हिंसक रास्ता अपना सकता है। लेकिन उम्मीद की किरण भी मौजूद है। नेपाल का नागरिक समाज सक्रिय और सशक्त है। उसकी बहुलतावादी राजनीति और सामाजिक एकजुटता हालात सुधारने का अवसर देती है।

समाधान की राह: चार स्तंभ

नेपाल की मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने के लिए चार स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाना ज़रूरी है।

राजनीतिक संवाद: सरकार को तुरंत सभी वर्गों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। आंदोलनकारी युवाओं में से ऐसे प्रतिनिधियों को चिन्हित करना होगा जो संवाद में भाग ले सकें। लोकतंत्र में सहमति ही सबसे बड़ा हथियार है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: राजनीतिक दलों और नेताओं की जवाबदेही तय की जाए। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए। भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मज़बूत किया जाए।

आर्थिक नवीनीकरण: युवाओं को रोज़गार के अवसर दिए जाएँ। उद्यमिता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले। कृषि और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में आधुनिक सुधार किए जाएँ।

डिजिटल स्वतंत्रता का संरक्षण

इंटरनेट पर सेंसरशिप की बजाय संवाद और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। युवा वर्ग को डिजिटल माध्यमों से रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। साइबर सुरक्षा और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता मिले। नेपाल का यह संकट केवल सत्ता संघर्ष नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी है। जेन-जी आंदोलन यह बताता है कि नई पीढ़ी अब पुरानी राजनीतिक संरचनाओं को आँख बंद करके स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह पारदर्शिता, ईमानदारी और बेहतर भविष्य की मांग कर रही है। इसलिए, सेना या बल प्रयोग से हालात नियंत्रित करने की बजाय राजनीतिक संवाद, सुधार और जनता की वास्तविक मांगों को स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। यदि नेपाल इस मौके पर गंभीरता से सुधारों को लागू करता है, तो यह संकट उसके लोकतंत्र को और मज़बूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर यह अवसर गंवा दिया गया, तो देश गहरी अस्थिरता और अविश्वास के दलदल में फँस सकता है। नेपाल की ताक़त उसकी जनता और विविधता है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इमारतें बदहाल क्यों?

-केवल बजट पास करने से नहीं, ज़मीनी निगरानी और प्राथमिकता जरूरी

शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति की नींव है। अगर नींव मजबूत न हो तो पूरा ढांचा अस्थिर हो जाता है। यही स्थिति आज राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के सरकारी स्कूलों की है। बच्चों को ज्ञान का उजाला देने वाली यह इमारतें खुद जर्जर होकर अंधकार का प्रतीक बन चुकी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षिक वातावरण देना सरकार का कर्तव्य है, इसे टालने की गुंजाइश नहीं है। बारिश के मौसम में कई स्कूलों की दीवारें और छतें गिर पड़ीं, बच्चों की जान पर बन आई। इसके बाद सरकार ने सफाई दी कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टेंट और टीन शेड लगा दिए गए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों सरकार को बच्चों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने के बजाय "लीपापोती" करने की आदत पड़ गई है?

सरकारी स्कूलों की मौजूदा तस्वीर

राजस्थान सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में लगभग 86,000 कक्षा-कक्ष जर्जर स्थिति में हैं। यानी हजारों-हजार बच्चे हर दिन ऐसी इमारतों में पढ़ने को मजबूर हैं, जहां छत कभी भी गिर सकती है, दीवारें किसी भी वक्त ढह सकती हैं। कई स्कूलों में खिड़कियाँ और दरवाज़े टूटे हुए हैं। बिजली की वायरिंग खराब है और बच्चों को करंट लगने का खतरा बना रहता है। पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी दयनीय स्थिति में हैं। बरसात में कक्षा-कक्ष में पानी भर जाता है और बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाल्टियों से पानी निकालने लगते हैं। यह तस्वीर बताती है कि "शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने" का दावा जमीनी स्तर पर कितना खोखला है।

समस्या की जड़: लापरवाही और दिखावटी सुधार

घोर लापरवाही – स्कूल भवन बनने के बाद उनकी नियमित मरम्मत और निगरानी का कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है। बरसों तक टेंडर पास नहीं होते और इमारतें जर्जर होती जाती हैं। बजट का गैर-इस्तेमाल – शिक्षा विभाग को हर साल भारी बजट मिलता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा वेतन, प्रशासनिक खर्च और कागजी योजनाओं में चला जाता है। भवन मरम्मत पर खर्च न के बराबर होता है। ठेकेदारी और भ्रष्टाचार – भवन निर्माण व मरम्मत का काम अक्सर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है, जो घटिया सामग्री का उपयोग करके खानापूरी कर देते हैं। न तो इंजीनियरिंग निरीक्षण होता है और न ही जवाबदेही तय की जाती है। आपातकालीन लीपापोती – जब हादसा होता है या मीडिया रिपोर्ट सामने आती है, तब सरकार टेंट और टीन शेड जैसी तात्कालिक व्यवस्था दिखा देती है। इससे असली समस्या जस की तस बनी रहती है।

सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव

बच्चों की सुरक्षा खतरे में: हर साल दीवार गिरने, छत ढहने जैसी घटनाओं में बच्चों के घायल होने या जान जाने की खबरें आती हैं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सीधा सामाजिक अपराध है।

पढ़ाई पर असर: जब बच्चे असुरक्षित और असुविधाजनक माहौल में पढ़ेंगे तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? शोरगुल, बारिश, धूल और अस्वस्थ वातावरण से पढ़ाई का स्तर नीचे गिरता है।

गरीब परिवारों पर असर: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब और ग्रामीण परिवारों से आते हैं। यदि उन्हें भी सुरक्षित शिक्षा नहीं मिलेगी तो समाज में असमानता और गहरी होगी।

निजी स्कूलों की ओर झुकाव: सरकारी स्कूलों की बदहाली से लोग बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर होते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़े। इससे आर्थिक असमानता और गहरी होती है।

न्यायपालिका का हस्तक्षेप: क्यों जरूरी?

हाईकोर्ट ने 15-18 सितंबर के

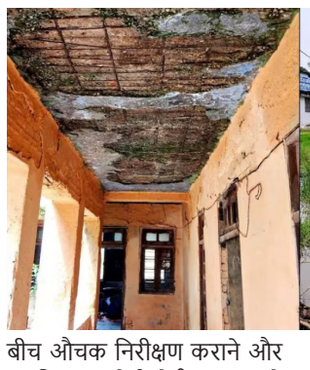

बीच औचक निरीक्षण कराने और 19 सितंबर को रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि टेंट व टीन शेड जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ बच्चों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्था को सुधारने में भी न्यायपालिका को दखल देना पड़ रहा है। यह प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। सरकारें केवल चुनावी घोषणाओं और योजनाओं की घोषणा में व्यस्त रहती हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देतीं।

समस्या के मूल कारण

निगरानी तंत्र की कमी – कोई स्पष्ट एजेंसी नहीं है जो समय-समय पर स्कूल भवनों की जांच करे और मरम्मत कराए। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी – शिक्षा को हमेशा वोट बैंक की राजनीति में नजरअंदाज किया जाता है। भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी – शिक्षा योजनाओं के पैसे भवन मरम्मत के बजाय दूसरी मदों में खप जाते हैं। जवाबदेही का अभाव – न तो इंजीनियर, न ठेकेदार और न ही शिक्षा अधिकारी किसी हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे देशों में स्कूल भवनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। हर 5 साल में इमारतों की संरचनात्मक जांच होती है। बच्चों के अनुकूल माहौल (रोशनी, हवा, तापमान, फर्नीचर) पर सरकार कड़ी निगरानी रखती है। किसी भी खराबी की सूचना मिलते ही तुरंत मरम्मत होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश में अगर यह सब संभव नहीं हो पा रहा है, तो यह केवल प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी दर्शाता है।

क्या होना चाहिए समाधान?

स्कूल भवन सुरक्षा ऑडिट: हर साल स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सभी स्कूलों की इमारतों की तकनीकी जांच हो।

मरम्मत के लिए अलग फंड: शिक्षा बजट में स्कूल मरम्मत और रख-रखाव के लिए अलग और सुरक्षित फंड बनाया जाए, जिसे किसी अन्य काम में खर्च न किया जा सके।

जवाबदेही तय करना: अगर किसी स्कूल में हादसा होता है तो संबंधित इंजीनियर, ठेकेदार और शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार माने जाएं और उन पर सख्त कार्रवाई हो।

समुदाय की भागीदारी: गांवों और कस्बों में स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिकार दिए जाएं कि वे भवन की स्थिति की निगरानी करें और छोटी-मोटी मरम्मत खुद करा सकें।

दीर्घकालिक योजना: केवल टेंट और टीन शेड पर निर्भर रहने के बजाय 5-10 साल की रणनीति बनाकर सभी जर्जर स्कूल भवनों को प्राथमिकता से नया बनाया जाए। निजी क्षेत्र और CSR सहयोग: कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कंपनियों को सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण में जोड़ा जा सकता है। सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं हैं, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की परीक्षा भी हैं। बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आधुनिक शैक्षिक वातावरण देना सरकार का कर्तव्य है।

राजस्थान को पर्यटन में बनायेंगे नंबर वन डेस्टिनेशन - उपमुख्यमंत्री

-पर्यटन विभाग जल्दी ही शुरू करेगा पर्यटन ऐप

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 की शुक्रवार को भव्य शुरुआत हुई। तीन दिवसीय इस महत्त्वपूर्ण आयोजन का पहला दिन राजस्थान की परंपरा और आधुनिकता के संगम का सजीव उदाहरण बना। सिटी पैलेस में हुए उद्घाटन सत्र में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान पर्यटन विभाग की कमिश्नर सुश्री रुक्मणि रियाड़, एफएचटीआर प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला, एफएचटीआर महासचिव सीए वीरेंद्र एस. शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र एस. शाहपुरा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की परंपरा, संस्कृति और मेहमाननवाज़ी हमारी असली ताक़त है। आरडीटीएम 2025 इसी पहचान को और सशक्त बनायेगा और राज्य को पर्यटन जगत की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दुनिया का नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है। हम जल्दी ही राजस्थान में पर्यटन ऐप शुरू करेंगे जिसकी सहायता से पर्यटकों को राजस्थान घूमना आसान हो जाएगा खासकर महिला पर्यटकों को यह पर्यटक ऐप राजस्थान घूमने के अनुभव को अच्छा और सुरक्षित बनाएगा। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में पर्यटक सुविधाओं का विकास कर रहें हैं। हम शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण का कार्य भी कर रहें हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर,कला, संस्कृति के संरक्षण पर हमारा विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ़ पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह निवेश, रोज़गार और स्थानीय समुदायों के विकास का भी सेतु है। आरडीटीएम के ज़रिए राजस्थान वैश्विक मानचित्र पर और भी मज़बूती से उभरेगा।

राजस्थान पर्यटन विभाग की कमिश्नर सुश्री रुक्मणि रियार ने कहा कि आरडीटीएम 2025 सिर्फ़ एक आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की बदलती हुई पर्यटन दृष्टि और संभावनाओं का प्रतिबिंब है। एफएचटीआर प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि आरडीटीएम 2025 ने साबित किया है कि जब परंपरा और आधुनिकता साथ आते हैं तो पर्यटन जगत को नई दिशा मिलती है।

इस अवसर पर पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। इस श्रृंखला में सीनियर होटलियर अजीत कुमार बंसल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया साथ ही Enduring Impact on Tourism & Administration पुरस्कार आईएएस निरंजन कुमार आर्य को प्रदान किया गया। Woman Empowerment in Hospitality & Tourism पुरस्कार आईएएस श्रीमती गायत्री राठौड़ को मिला। Legacy of Heritage & Tourism पुरस्कार सामोद होटल्स (रावल रघुवेंद्र सिंह एवं रावल यदुवेंद्र सिंह सामोद) को दिया गया। इसके साथ ही Hall of Fame पुरस्कार इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स के पूर्व प्रेसिडेंट राजीव मेहरा को तथा Outstanding Journalism - Wildlife & Tourism पुरस्कार सीनियर जर्नलिस्ट निर्मल तिवारी को प्रदान किया गया।

बी2बी मीटिंग्स और एक्सपो रहेंगे मुख्य आकर्षण-

13 और 14 सितम्बर को बी.एम. बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बी2बी मीटिंग्स और एक्सपो का आयोजन होगा। इस दौरान आगंतुकों को टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाओं का 'वन स्टॉप सल्युशन' मिलेगा। साथ ही, आम जनता के लिए खुली प्रदर्शनी पर्यटन के विविध और समृद्ध आयामों को अनुभव करने का मंच बनेगी। पिछले संस्करण की तुलना में इस बार सहभागिता कहीं अधिक व्यापक है। बड़ी संख्या में भागीदारी से यह उम्मीद और प्रबल हुई है कि राजस्थान न केवल आयोजनों की धरती है, बल्कि अनुभवों, सांस्कृतिक धरोहर और व्यावसायिक अवसरों का जीवंत संगम है।

पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रभावित परिवारों को दी सहायता

-खाद्य सामग्री, शिक्षण सामग्री व कपड़े किए भेंट

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने अजमेर उत्तर विधानसभा के स्वास्तिक नगर में आज बोराज तालाब की पाल टूटने से प्रभावित परिवारों को सहायता भेंट की। राहत शिविर के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद्य सामग्री, शिक्षण सामग्री व वस्त्र भेंट किए। लोगों को आटे के कट्टा, चावल, तेल, साबुन सहित एक महीने की खाद्य सामग्री दी गई। इसके अलावा बच्चों को स्कूल ड्रेस, टीशर्ट, लोवर, बिस्तर भी दिए गए। साथ ही लोगों के घरों में जाकर आंखों से नुकसान को देखा और सरकार से राहत दिलाने की बात कही।

पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि स्वास्तिक नगर, विनायक नगर व रावत कॉलोनी में बोराज तालाब टूटने से लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तालाब टूटने की आपदा आने के बाद उत्तर विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपनी टीमों के साथ लोगो की मदद के लिए कार्य कर रहे है। लगातार भोजन व राहत सामग्री वितरित कर पीड़ित परिवारों की सहायता कर रहे है। आपदा के बाद उत्तर विधानसभा कांग्रेस की टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया और नुकसान की रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सर्वे रिपोर्ट देंगे। ताकि लोगों को सही समय पर मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहां का दौरा किया था और पीड़ित लोगों से मिले थे और सरकार से शीघ्र राहत देने की मांग की थी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्पित होकर पीड़ितों की सेवा कर रहे है। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन के स्तर पर पीड़ित लोगों को नाम मात्र की राहत दी जा रही है।जिस पर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई। पीड़ित लोगो ने मुझसे कहा कि प्रशासन के अधिकारियों ने नुकसान की भरपाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, अब तक सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही है, जबकि लोग खाने पीने के लिए तड़प रहे है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल पीड़ित लोगो को तत्काल स्पेशल पैकेज देकर राहत प्रदान करे, ताकि लोगों को कुछ मदद मिल सके। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी लोगों को राहत दिलाने के टॉस कदम उठाए, क्योंकि यह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का विधानसभा सभा क्षेत्र है। राठौड़ ने कहा कि जब स्वास्तिक नगर के हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक राशन सामग्री, शिक्षण, कपड़े की सेवा जारी रहेगी। इस दौरान राठौड़ ने लोगो की समस्या का समाधान करने के लिए एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ से भी बातचीत की।

इस दौरान पार्षद पूर्व विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजुकमार जयपाल, नोरत गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेन्द्र अग्रवाल, वाहिद मोहम्मद, पूर्व पार्षद सर्वेश पारीक, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल, सेवादल शहर अध्यक्ष देशराज मेहरा, , मंडल अध्यक्ष छोटू सिंह रावत, भंवर सिंह राठौड़, पंकज छोटवानी, निमेष चौहान, हेमंत जसोरिया, राजेश गोड़ीवाल, निर्मल पारीक सुमित मित्तल, विकास चौहान, पीयूष सुराणा, महेंद्र जोधा, आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राजस्थान में 9 हजार 763 नये आवासों को मिली मंजूरी

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने के विजन को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. प्रदेश सरकार ने 9 हजार 763 नये आवासों को केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को आज बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एसएलएसएमसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन आवासों के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1.50 लाख रुपए केन्द्र सरकार और एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जायेगा। इस निर्णय से कुल 244.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी पात्र परिवारों को उपलब्ध होगी। इन आवासों की अंतिम स्वीकृति केन्द्र सरकार की 17 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली सीएसएमसी की बैठक में प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किये जा रहे प्रयास न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे बल्कि उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेंगे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग नवीन जैन, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध खनन और नियम विरुद्ध परिवहन रोकने के लिए विभागीय समन्वय से अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करें- संसदीय कार्य मंत्री

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में जोधपुर में लूणी नदी के लीज एरिया एवं नदी क्षेत्र के आस-पास से अवैध रूप से निकलने वाले डम्परों के ओवरलोड एवं अत्यधिक तेज गति के कारण हो रही दुर्घटनाओं और सड़क तंत्र की बर्बादी रोकने के संबंध में समीक्षा बैठक शुक्रवार को मारवाड़ इन्टरनेशनल सेन्टर में आयोजित हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा लूणी क्षेत्र में अवैध खनन और नियम विरुद्ध परिवहन रोकने के लिए विभागीय समन्वय से अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए लीज क्षेत्र के सीमांकन, पीलर निर्माण, जियो टैगिंग और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी एवं जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई - रवन्ना में अधिक समय, एक ही रवन्ना का अधिक बार उपयोग, फर्जी रवन्ना की नियमित जांच करने के निर्देश दिए।

पटेल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को खनन क्षेत्र में ओवर लोड परिवहन, बिना नंबर के वाहन पर आवश्यक कार्यवाही करने, व्यावसायिक वाहनों पर गति नियंत्रण नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने और फ्लाइंग टीम को माइनिंग रूट पर नियुक्त करने के निर्देश दिए।

टेल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खनन क्षेत्र में ओवर लोडिग वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपोर्ट बनाने, आबादी वाले क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर लगाने और खनन क्षेत्र में उच्च यात्री भार के अनुरूप सड़क निर्माण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को डम्परों की सड़क पर पार्किंग रोकने,बिना नंबर के वाहनों एवं ओवर स्पीड वाहनों की आबादी क्षेत्रों में आवाजाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मालवीय नगर जोन में जर्जर भवन को किया सीज

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन में शुक्रवार को भूखण्ड संख्या 676 पुरानी हवेली (रामपुरारूपा जेपी कॉलोनी के पास) को उपायुक्त प्रियवृत्त सिंह चारण के निर्देशन में भवन निर्माण शाखा की टीम एवं सतर्कता शाखा द्वारा जर्जर भवन को खाली करवाकर सीज की कार्रवाई की गई।

उपायुक्त प्रियवृत्त सिंह चारण ने बताया कि मालवीय नगर जोन क्षेत्र के भूखण्ड संख्या 676 के जर्जर अवस्था में था जिसके भवन स्वामी को जोन द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई एवं समझाइश की गई परन्तु भवन स्वामी द्वारा भवन को खाली नहीं किया गया। इसलिये कोई भी जनहानि ना हो इसलिये शुक्रवार को टीमों द्वारा इसे सीज किया गया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 13 को त्रिवेणी में आएंगे, पावटा में होगा स्वागत

मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आगमन 13 सितम्बर 2025 को प्रातः 8 बजे पावटा मैन स्टैंड पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रातः 9 बजे त्रिवेणी धाम में जाएंगे। इस शुभ अवसर पर वे त्रिवेणी धाम में विराजमान परम पूज्य महाराज श्री के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

पूर्व सरपंच मदन लाल यादव ने बताया कि उनका यह दौरा न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए भी अत्यंत हर्ष का विषय है। त्रिवेणी धाम जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत पावन स्थल है, वहाँ केंद्रीय मंत्री का आगमन पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। भूपेंद्र यादव का यह दौरा सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना को और अधिक प्रबल करेगा।

14 को खाकीशाह बाबा का 828 वां उर्स

-चद्दर के जुलूस में उमड़ेगी आस्था की गंगा

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। कस्बें के खाकिशाह मोहल्ला में विराजमान हिन्द मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत खाकीशाह बाबा का 828 वां एक दिवसीय वार्षिक उर्स 14 सितंबर रविवार को आस्था और अकीदत में आयोजित होगा। दरगाह कमेटी की बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। डॉक्टर शकील शाह ने बताया कि रविवार की सुबह 8 बजे कुरान ख्वानी के साथ उर्स का आगाज होगा। इसी के साथ मे रंग बिरंगे परिधानों में सज संवर कर विभिन्न वाहनों पर सवार होकर जायरिनों का आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोपहर जौहर की नमाज के बाद होद पाल से चादर जुलूस रवाना होगा, जो कि गांधी चौक बाजार से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचेगा। इस दौरान बाबा को चाहने वाले हिन्द मुस्लिम लोग जुलूस पर पुष्पवर्षा करेंगे।

दरगाह प्रांगण में जुलूस जाकर बाबा के आस्ताने पर चादर चढ़ाई जाएगी।

इस दौरान भारत देश की सलामती की दुआएं की जाएगी। दरगाह परिसर में आकर्षक व मनमोहक विधुत सजावट की जाएगी। दूर-दराज से आने वाले जायरीन के लिए दरगाह कमेटी और प्रशासन ने व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की है। कस्बे में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम रहेंगा।

खाकीशाह बाबा के उर्स को लेकर अकीदतमंदों में जबरदस्त उत्साह है और नगर में शुक्रवार से ही चहल-पहल शुरू हो गई है। शाम को 6 बजे बाद लंगर वितरण किया जाएगा जिसमे बाबा को चाहने वाले अकीदतमंद पंगत प्रसादी लेंगे। रात्रि 10 बजे बाद में महफ़िल-ए-शमा का आयोजन किया जाएगा। जिसमे बॉम्बे के सलीम राजा द्वारा बाबा की मान मनुहार की जाएगी। इस दौरान निजामुद्दीन काजी सदर, जम्मू शाह (जमील) खादिम, उस्मान शाह सदर, लियाकत शाह सदर आदि उर्स की रूपरेखा देख रहे है।

शिक्षा मंत्री ने किया कोटा शहर के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया

-विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा देने पर दिया जोर

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को कोटा शहर में कुछ सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आवासन मंडल स्कूल, केशवपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल परिसर और कक्षा कक्षों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा विद्यालय प्रशासन को नियमित स्वच्छता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया। दिलावर ने स्कूल में स्टाफ की उपस्थिति और बच्चों की संख्या को लेकर भी जानकारी ली।

इसके बाद शिक्षा मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से खेल सामग्री व खेल के नियमित कालांश के सम्बंध में जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद भी आवश्यक है। विद्यालयों में खेल सामग्री पहुंचा दी गई है, अब बच्चों को खेलने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाए तथा खेल के कालांश नियमित रखे जाएं।

शिक्षा मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालाकुंड का भी निरीक्षण किया तथा स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। मंत्री दिलावर ने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने तथा बच्चों को संस्कारित करने के भी शिक्षकों को निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि तीनों ही स्कूलों में व्यवस्थाएं उपयुक्त हैं परंतु शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता पर और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर के लिए रवाना हो गए।

नगर निगम ग्रेटर सतर्कता शाखा की बड़ी कार्रवाई

-1 हजार रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 4 केन्टर सामान जब्त

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में करतारपुरा नाले के आस-पास से, सूर्य नगर 60 फीट रोड़, गोपालपुरा बाईपास से सुदामा कुट्टी तक अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 1 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 4 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में करतारपुरा नाले के आस-पास से, सूर्य नगर 60 फीट रोड़, गोपालपुरा बाईपास से सुदामा कुट्टी तक अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 4 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 1 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध चलाया गया विशेष अभियान

-1 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक 11 लाख 25 हजार 200 रुपये का किया कैंरिग चार्ज

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 1 से 10 सितंबर 2025 तक मात्र 10 दिनों में जोनवार चालानी कार्रवाई की गई जिसके तहत सभी जोनों से कुल 11 लाख 25 हजार रुपए वसूले गए।

आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि 1 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष अभियान के तहत नगर निगम ग्रेटर की टीमों एवं स्वच्छता प्रहरी टीम द्वारा दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि मानसरोवर जोन में 2 लाख 97 हजार रूपये, सांगानेर जोन में 2 लाख 3 हजार रूपये, जगतपुरा जोन में 1 लाख 44 हजार 900 रूपये, झोटवाड़ा जोन में 1 लाख 32 हजार 200 रूपये, मालवीय नगर जोन में 1 लाख 30 हजार 800 रूपये, विद्याधर नगर जोन में 1 लाख 21 हजार 600 रूपये, मुरलीपुरा जोन में 95 हजार 700 रूपये का कैंरिग चार्ज वसूल किया गया।

हज़रत सय्यद ज़ुल्फ़िक़ार अली शाह रह. का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स सम्पन

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर जिले की आमेर तहसील की घाटी में स्तिथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हज़रत सय्यद ज़ुल्फ़िक़ार अली शाह रह. का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स कूल की रस्म के साथ विधिवत सम्पन हो गया। सूफ़ी अब्दुल रज्जाक खान शेख (ताला) ने बताया अंग्रेजी तारीख 10 सितम्बर बुधवार व चाँद की तारीख 17 रबी उल अवल को सुबह झंडा फहराया गया इसी के साथ रंग बिरंगे कपड़ो में सज संवर कर विभिन्न प्रकार के वाहनों में सवार होकर जायरीनों के जत्थे आना शुरू हुए, रात को ईशा के बाद मिलाद शरिफ हुई जिसमे ख़ुदा के हुकम व मोहम्मद (स.अ.व.स.) के तरीके पर चलने की बात कही गई। 11 सितम्बर गुरुवार को राजस्थान की प्रसिद्ध कव्वाल पार्टियों के संग चादर का जुलूस निकला व बाबा के चाद्दर पेश की गई। इसके बाद में सम्पूर्ण रात्रि तक राजस्थान की प्रसिद्ध कव्वाल पार्टियों के द्वारा बाबा की मान मनुहार की गई।

इसी प्रकार अंग्रेजी तारीख 12 सितम्बर शुक्रवार व चाँद की तारीख 19 रबी उल अवल को सुबह 10 बजे फ़ातेहा व कूल और लंगर हुआ इसमे सामूहिक कव्वाल पार्टियों द्वारा बाबा की मान मनुहार करते हुए कूल की रस्म की अदायगी हुई इसी के साथ विधिवत रस्म ओ रिवाज के उर्स का समापन हुआ। लंगर (पंगत प्रसादी) के दौरान अकीदतमंदों द्वारा लंगर खाए इसी दौरान गठजोड़ा, मुंडन व चाद्दर चढ़ाने सहित आदि कार्यक्रम भी हुए।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए	
टोल फ्री नंबर	18001806507
वॉट्सएप नंबर	9414037085
कस्टमर केयर	2203000
आईवीआरएस	1912
कचरा गाड़ी के लिए	
ग्रेटर	2747400
सीवरेज लीकेज	2607500
हेरिटेज	2607500
टोल फ्री नंबर	14420
पुलिस की मदद के लिए	
साइबर क्राइम	1930/2360094
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	1090
मुख्यमंत्री पोर्टल	181
पानी के लिए	
जलदाय कार्यालय	2706624
फायर ब्रिगेड	2747400
मेडिकल इमरजेंसी के लिए	
एंबुलेंस	102/108
एसएमएस इमरजेंसी	2518333
महिला चिकित्सालय	22610616
जनाना हॉस्पिटल	22378721
SDMH	22574189
SMS ब्लड बैंक	22518222
कल्याण ब्लड बैंक	22721771
घायल पशुओं के लिए	
नगर निगम	2747400
बर्ड बाइक	9887345580
हेल्प इन सफरिंग	8107299711
जनमंच ट्रस्ट	7230055800
पशु चिकित्सालय	2747400

राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में पोक्सो एक्ट पर आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित

बारां (रॉयल पत्रिका)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार मिशन शक्ति योजना के तहत चल रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां में पोक्सो एक्ट विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सतीश परिहार ने किया। उन्होंने विभागीय योजनाओं जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना तथा नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत निशुल्क आरएससीआईटी, आरएस-सीएसईपी, आरएस-सीएफए कोर्स की जानकारी दी और अधिक से अधिक नामांकन हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जेंडर स्पेशलिस्ट पुष्पा शर्मा ने पोक्सो एक्ट (2012) की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने गलत तरीके से छूना, अश्लील वीडियो दिखाना जैसे अपराधों पर चर्चा की और बताया कि यह कानून बालक व बालिका दोनों पर समान रूप से लागू है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में भी जानकारी दी। सुपरवाइजर मोनिका शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिला हेल्पलाइन 181 सहित अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं डॉ. खुशबु निपरता ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव के उपाय बताए। डॉ. लीनता अरोड़ा ने कालीबाई भील योजना की जानकारी दी और डॉ. हिमानी भाटिया ने शिक्षा के महत्व पर विचार साझा किए। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मुनेश चंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को जागरूक रहकर विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सहायक निदेशक सतीश परिहार ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जेंडर स्पेशलिस्ट पुष्पा शर्मा ने पोक्सो एक्ट ;2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने गलत तरीके से छूना, अश्लील वीडियो दिखाना जैसे अपराधों पर चर्चा की और बताया कि यह कानून बालक व बालिका दोनों पर समान रूप से लागू है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में भी जानकारी दी। सुपरवाइजर मोनिका शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिला हेल्पलाइन 181 सहित अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं डॉ. खुशबु निपरता ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव के उपाय बताए। डॉ. लीनता अरोड़ा ने कालीबाई भील योजना की जानकारी दी और डॉण् हिमानी भाटिया ने शिक्षा के महत्व पर विचार साझा किए। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मुनेश चंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को जागरूक रहकर विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सहायक निदेशक सतीश परिहार ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

अखिल भारतीय अग्रवाल महिला जिला संगठन इकाई बारां की अनूठी पहल

-मियाडा गाँव स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को गोद

बारां (रॉयल पत्रिका)। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला जिला संगठन इकाई बारां की जिला अध्यक्ष नीतु गुप्ता ने समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए मियाडा गाँव स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को गोद लिया। विद्यालय को गोद लेने के उपलक्ष में बच्चों को स्कूल बैग और पठन सामग्री वितरित की गई, जिसमें नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, कलर बॉक्स आदि शामिल थे। इस अवसर पर जिला महामंत्री मधु गोयनका ने बताया कि "संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इस प्रकार की पहल से बच्चे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे।" इस अवसर पर नीतु गुप्ता ने भी कहा कि शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है, और हमारा प्रयास रहेगा कि विद्यालय के हर बच्चे को अच्छे संसाधन उपलब्ध हों और वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें कोषाध्यक्ष हेमलता गर्ग व बबली अग्रवाल का भी विशेष सहयोग रहा संगठन की सीनियर व सहलाकर मंत्री सुनीला अग्रवाल उषा गोयल व मंजू गोयल ने बच्चों से जनरल नॉलेज के प्रश्न उतर पूछे और विजेताओं को पारितोषिक वितरण किए इस अवसर पर मनीषा गोयल व सुशीला बंसल का भी विशेष सहयोग रहा। गाँव वासियों और संगठन की सदस्याओं ने इस कदम का हृदय से स्वागत किया और इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बताया।प्रधानाध्यापक रंजना शर्मा ने सभी का बहुत आभार व्यक्त किया ओर आगे भी सहायता करने की अपील की।

अंता उप चुनाव को लेकर व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा बैठक

शब्बीर हुसैन

बारां (रॉयल पत्रिका)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने संभावित आगामी विधानसभा अंता उप चुनाव 2025 के दृष्टिगत मिनी सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित कर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन क्षेत्रवार व्यय संवेदनशील पोकेट्स एवं स्थानों की पहचान कर सतर्कता बरती जाए तथा समय रहते ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर निर्वाचन समन्वयक हीरालाल वर्मा, जिला परिषद सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, डीटीओ डॉ. कल्पना शर्मा, आबकारी अधिकारी देवेन गिरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य पुरस्कार गाइड प्रशिक्षण शिविर का सहायक स्टेट कमिश्नर गाइड ने किया अवलोकन

राष्ट्रपति अवार्ड का लक्ष्य रखे गाइड- नूतन बाला कपिला

पाली (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय पाली के तत्वावधान में दिनांक 10 से 14 जून 2025 तक राज्य पुरस्कार गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला प्रशिक्षण केंद्र बजरंग बाड़ी पाली में किया जा रहा है। सीओ गाइड डिंपल दवे ने बताया कि शिविर के तृतीय दिवस आज सहायक स्टेट कमिश्नर गाइड नूतन बाला कपिला ने शिविर का अवलोकन किया एवं गाइड से राज्य पुरस्कार शिविर के अनुभव एवं गतिविधियों का जायजा लिया। नूतन बाला कपिला ने गाइड को उद्बोधन प्रदान करते हुए केवल राज्यपाल अवार्ड तक स्वयं का सिमीत नहीं रखे ओर सभी गाइड राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, गाइड को यूज एंड थ्रो पलास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलवाई ओर प्लास्टिक उन्मूलन का संदेश प्रदान करते हुए कपड़े के बैग वितरित किए। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर लौटे रोवर विशाल का स्कार्फ पहनाकर सम्मानित एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पुष्पा परिहार, लीला जैन, तारा चंद जैन, शशि लोढ़ा, कैलाश कुमार सचिव पाली ओर प्रदीप कुमार शर्मा सचिव गुंदोज आदि उपस्थित रहे। सीओ स्काउट गोविन्द मीना ने बताया कि 05 दिवसीय शिविर में गाइड द्वारा प्रातःकालीन व्यायाम सत्र से लेकर रात्रिकालीन शिविर जीवन के प्रत्येक गतिविधियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जा रहा है। प्रशिक्षण - प्रशिक्षण विषयों में बी पी सिक्स व्यायाम, ध्वजारोहण, निरीक्षण, गैजेट बनाना, गांठें लगाना, गणवेश धारण करना, दक्षता पदक की जानकारी, सेवा लॉगबुक का संधारण आदि विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 05 दिवसीय राज्य पुरस्कार गाइड प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक के रूप में सहायक लीडर ट्रेनर उर्मिला यति, नसीम बानो, अलका टाक, कमलेशी मीणा, खुशबू , विश्वा, सुमित्रा आदि के द्वारा प्रशिक्षण एवं रोवर विशाल, भीमाराम, करण, हेमराज, हिमांशु, कैलाश, घीसाराम व रेंजर काव्या द्वारा शिविर में सेवाएं प्रदान की जा रही है।

चौमूं NH52 पर टूटी सड़क और लापरवाही से परेशान लोग, ग्रामीणों ने जताया विरोध

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। चौमूं के NH52 पर जगह-जगह टूटी सड़क से आवागमन में परेशानी..! NHAI के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर कोई ध्यान। चौमूं के जैतपुरा में पुलिया निर्माण कंपनी के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध चौमूं हाइवे पर हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य चौमूं में हाइवे निर्माण कार्य में लापरवाही के खिलाफ स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, ट्रैफिक को किया गया सर्विस रोड पर डायवर्ट, लेकिन सर्विस रोड जगह-जगह टूटी-फूटी हालत में, हाइवे पुलिया निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली मिट्टी धूल से स्थानीय दुकानदार काफी परेशान, सैकड़ो की संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा को करवाई शिकायत दर्ज ।चौमूं में हाइवे पर कंस्ट्रक्शन निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते बने रहते हैं जाम के हालात।

क्षतिग्रस्त पुलिया का केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने किया निरीक्षण

-पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मौके पर बुलाकर शुरू कराया मरम्मत कार्य

पाली (रॉयल पत्रिका)। अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पुलिया का शुक्रवार को केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मौके पर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को बुलाकर सुरक्षा जांच के बाद दोपहिया व तिपहिया वाहनों का आवागमन तुरंत शुरू कराया। उन्होंने बताया कि पुलिया से भारी वाहनों की आवाजाही अभी कुछ दिन बाद शुरू हो पाएगी। इस दौरान राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर के सांसद लुंबाराम चौधरी, सिरोही रक्षा भंडारी, पूर्व विधायक तारा भंडारी, ताराराम कुमावत, मंडल अध्यक्ष पोसालिया प्रताप परमार, हिम्मत दाना, रविकांत रावल, अध्यक्ष कुंदनमल राठी, महेंद्र माली, रमेश बोहरा, सुमेरपुर नगरपालिका के उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, पूनम सिंह परमार, सुमेरपुर एसडीएम कालूराम कुम्हार, नगरपालिका के पूर्व चौयरमैन राजेंद्र सोलंकी सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे।

25.66 करोड़ से बनेगा नया पुल , शिलान्यास जल्द केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि शिवगंज-सुमेरपुर को जोड़ने वाले इस पुल का पुनःनिर्माण किया जाएग इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष-2024-25 के बजट में पुल निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने संशोधित प्रस्ताव बनाया जिसके बाद 25.66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बारिश का सीजन खत्म होने के बाद पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर शुरू कराया जाएगा।

ग़रीब मज़दूर पिता को मिला न्याय : बेटे की मौत पर पाँच लाख की राहत

-वकीलों की जिद ने फिर जगाया विश्वास

-न्यायपालिका पर भरोसा – आम आदमी की बड़ी जीत

जयपुर/बारां (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान के बारां ज़िले के मांगरोल कस्बे के महावीर प्रसाद रैगर, जो दिहाड़ी मज़दूरी से अपने परिवार का पालन करते हैं, ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके छोटे से बेटे भूनेश (3 वर्ष) की दुर्घटनात्मक मौत के बाद न्याय पाने के लिए उन्हें इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बेटे की मौत छत से गिरने से 10 अप्रैल 2024 को हुई थी। सदमे और गरीबी के कारण न एफआईआर दर्ज हुई और न पोस्टमार्टम। जब उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत ₹5 लाख की सहायता राशि के लिए आवेदन किया, तो विभाग ने दस्तावेज़ों की कमी बताकर दावा ठुकरा दिया। इस कठिन लड़ाई में महावीर प्रसाद के साथ खड़े हुए अधिवक्ता अंसार इंदौरी और अजीत कस्वां। दोनों ही वकील लंबे समय से संविधानिक अधिकारों और आमजन के हक़ के लिए न्यायालय में संघर्षरत हैं। उन्होंने इस मामले को सिर्फ़ एक मुआवज़े की लड़ाई नहीं माना, बल्कि न्यायपालिका में ग़रीब आदमी के विश्वास को बचाने का संघर्ष समझा। हाईकोर्ट, जयपुर बेंच में दायर याचिका पर माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंढ ने आदेश दिया कि महावीर प्रसाद की अपील बीमा विभाग को प्राथमिकता से निपटानी होगी। आदेश के बाद, आखिरकार महावीर प्रसाद के खाते में पूरे पांच लाख ₹5,00,000/- की राशि पहुँच गई। महावीर प्रसाद भावुक होकर कहते हैं "हम ग़रीबों के लिए अदालत ही भगवान है। बेटा तो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन न्यायपालिका और हमारे वकीलों ने हमें सहारा दिया। अगर वे नहीं लड़ते तो हमें कुछ भी नसीब नहीं होता।"

संविधानिक संघर्ष की मिसाल अधिवक्ता अजीत कस्वां और अंसार इंदौरी ने कहा यह केवल पाँच लाख रुपये का मामला नहीं था, बल्कि यह उन सभी ग़रीब और मज़लूम परिवारों की आवाज़ थी जिन्हें सिस्टम अकसर ठुकरा देता है। हमारा उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक न्याय पहुँचाना है, जो संविधानिक अधिकारों का हक़दार है। उनकी यह लड़ाई इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका आज भी आम नागरिक की सबसे बड़ी ढाल है और वकीलों का संवेदनशील दृष्टिकोण ही समाज को न्याय के क़रीब लाता है। न्यायपालिका ग़रीब की भी सुनती है। संविधान के अधिकार केवल काग़ज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी लागू हो सकते हैं। वकीलों का संघर्ष समाज के सबसे वंचित वर्गों को नया जीवन देता है। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ़ एक पिता को आर्थिक राहत देने का मामला नहीं, बल्कि न्यायपालिका और अधिवक्ताओं पर आम आदमी के विश्वास को मजबूत करने वाला राष्ट्रीय महत्व का उदाहरण है।

मर्कजी मस्जिद व्यापारियन की तरफ से पंजाब बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए खाद्य सामग्री की गाड़ियां रवाना की

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर मर्कजी मस्जिद व्यापारीयान की तरफ से 5 पिकअप गाड़ी पंजाब में खाद्य सामग्री लेकर रवाना हुई जिसे जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले शुक्रवार की नमाज अदा कर मर्कजी मस्जिद मोहल्ला व्यापारियन ने मस्जिद के आगे से मोहल्ले वासियों ने बाढ़ग्रस्त इलाके के जरूर सामान एव खाद्य सामग्री दुआ के साथ रवाना की और मस्जिद इमाम मौलाना इमरान ने कहा जहाँ सैलाब की बेरहम लहरों ने तबाही के मंजर बिखेर दिए जो दिलों को झंझोडती और रूहों को बेदार करती है। दुनिया के एक सच्चे रइसी हजरत मो. मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीजा रौशनी में उम्मते मुसलमाँ को उम्मे अजीम दीनी फरीजे की याद धानी कराई कि मजलूमों और मुसीबत जरों का सहारा बनना इस्लाम का अहम् फरीजा है। उसी वक़्त मरकज मस्जिद के इमाम मौलाना मो. इमरान ने दृढ संकल्प लिया और मस्जिद के मुक़द्दस मेम्बर से अपील की हमारे प्यारे देश के सूबा पंजाब की मदद के लिए हम सब भाई कंधे से कंधे मिलाकर अपने भाइयों की जान व माल से मदद करें, जब हमारा देश मुसीबत की चादर ओढे हो तो उस वक़्त हमारा खामोश रहना मुसलमान की शान के खिलाफ है। इम्तिहान कि इस घडी में हमने अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया और मरकज़ इमाम मौलाना इमरान ने तमाम मुसलमान भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा किया और दुआ की अल्लाह पाक दुनिया और आखरत में इसका बहतर दर्जा दें ।

शहर चलो अभियान 15 से, वार्डवार शिविरों का होगा आयोजन

शब्बीर हुसैन

बारां, (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहर चलो अभियान 2025 के तहत 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक जिले के नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में वार्डवार कलस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें 55 तरह के काम किए जाएंगे। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित कार्य भी इसमें होंगे।

पहले दिन नगर परिषद बारां के वार्ड संख्या 1 से 4, नगर पालिका अटरू के वार्ड 1 व 2, अन्ता के वार्ड 3 से 7, मांगरोल के वार्ड 1 से 6, सीसवाली के वार्ड 1 से 4 एवं छबड़ा के वार्ड 1 से 5 में शिविर लगाए जाएंगे। 16 सितम्बर को बारां नगर परिषद के वार्ड 4 से 7, अटरू के वार्ड 3 व 4, मांगरोल के वार्ड 1 से 6, सीसवाली के वार्ड 1 से 4 एवं छबड़ा के वार्ड 1 से 5 में शिविर होंगे।

अभियान में 17 सितम्बर को नगर परिषद बारां के वार्ड 7, 8 एवं 10, अटरू के वार्ड 5 व 6, अन्ता के वार्ड 1, 2, 29 व 35, मांगरोल के वार्ड 1 से 6, सीसवाली के वार्ड 1 से 4 तथा छबड़ा के वार्ड 6 से 10 में कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 18 सितम्बर को बारां के वार्ड 9, 11, 12, 13, अटरू के वार्ड 7 व 8, अन्ता के वार्ड 1, 2, 29, 35, मांगरोल के वार्ड 7 से 12, सीसवाली के वार्ड 5 से 7 और छबड़ा के वार्ड 6 से 10 में आयोजन होगा।

इसी प्रकार 19 सितम्बर को नगर परिषद बारां के वार्ड 13, 14, 15, अटरू के वार्ड 9 व 10, अन्ता के वार्ड 13, 14, 15, 31, 32, 33 व 34, मांगरोल के वार्ड 7 से 12, सीसवाली के वार्ड 5 से 7 एवं छबड़ा के वार्ड 11 से 16 में शिविर होंगे। वहीं 20 सितम्बर को बारां नगर परिषद के वार्ड 16 से 21, अटरू के वार्ड 11 व 12, अन्ता के वार्ड 13, 14, 15, 31, 32, 33 व 34, मांगरोल के वार्ड 13 से 18, सीसवाली के वार्ड 8 से 11 और छबड़ा के वार्ड 11 से 16 में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी, पंजीयन एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

यह होंगे कार्य

शिविरों में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, क्षतिग्रस्त सड़क पर पैचवर्क और सार्वजनिक पार्क व शौचालयों की मरम्मत, कार्यों की लंबित पत्रावलियों का निस्तारण, भू उपयोग परिवर्तन, नामांतरण व भवन निर्माण मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन सामाजिक सुरक्षा व योजनाओं के आवेदन, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने के कार्य किए जाएंगे। साथ ही सुनसान सड़कों पर विद्त व्यवस्था की जाएगी। लावारिस मवेशियों को पकड़ा जाएगा। सरकारी दस्तावेज, पट्टे, उप विभाजन, नामांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

घंटेल के राकेश स्वामी बने इंस्पेक्टर

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव घंटेल के राकेश स्वामी राजस्थान पुलिस की विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण कर इंस्पेक्टर के पद पदोन्नत हुए हैं। गौरतलब है कि राकेश के पिता ओमप्रकाश बरोला एवं दादा सहित परिवार के अनेक सदस्य पुलिस सेवा में अनेक पदों पर वर्तमान में कार्यरत व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राकेश अपनी ईमानदार छवि और हाल ही हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय बार्डर क्षेत्र के पुलिस थाना रणजीतपुरा (बीकानेर) में बीएसएफ के साथ मिलकर विशेष सजगता के साथ ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पिता ओमप्रकाश बरोला की प्रेरणा एवं अपने परिवारजनों के सहयोग को दिया है।

शिविर में तीन ट्राइसाइकिलों का वितरण

बारां (रॉयल पत्रिका)। सशक्त बारां प्रगति को शक्ति अभियान के तहत विशेष योग्यजनों को संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग, उपकरण योजना 2025 के अंतर्गत विशेष योग्यजनो को सहायता कृत्रिम अंग, उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए शुक्रवार को किशनगंज में विशेष योग्यजनों के चिन्हीकरण व पंजीयन के लिए शिविर का आयोजन किया गया।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी शुभम नागर ने बताया कि जिले की पंचायत शिविर में 52 विशेष योग्यजनों का पंजीयन किया गया। इनमें पात्रता के अनुसार आठ दिव्यांग प्रमाण पत्र, छह यूडीआईडी कार्ड, चार ट्राईसाइकिल, छह मोट्राइज्ड ट्राइसाइकिल, तीन बैशाखी, एक व्हील चेयर, एक श्रवण यंत्र आदि के आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में विशेष योग्यजनों को तीन ट्राइसाइकिल, एक बैसाखी का वितरण किया गया। सोमवार को पंचायत समिति शाहबाद में शिविर आयोजित होगा। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन, पालनहार योजना का सत्यापन, सुखद दाम्पत योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना एवं दिव्यांग सहायक अंग, उपकरण आदि के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

अंता विधानसभा उपचुनाव मतदाता सूची के लिए विशेष अभियान रविवार को

बारां (रॉयल पत्रिका)। जिले की अंता विधानसभा के उपचुनाव के तहत मतदाता सूची के लिए सभी प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 25 सितम्बर तक किया जाएगा। इसके उपरांत 1 अक्टूबर, 2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि बताया कि मतदाता सूची संबंधित कार्य के लिए 14 सितम्बर (रविवार) को विशेष अभियान तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन विधानसभा क्षेत्र अंता के सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेंगे और दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य आयोजना अधिकारी रुद्रा रेणु ने 20 सूत्री कार्यक्रम की सम्बंधित विभागों की माह अगस्त की मासिक प्रगति से अवगत कराया। माह अगस्त की प्रगति के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम में राजीविका के सूत्र एसएचजी प्रमोटेड व रिवॉल्विंग फण्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्थानीय निकाय के सूत्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्र संस्थागत प्रसव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सूत्र व सार्वजनिक निर्माण विभाग के सूत्रों में आवण्टित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि कम रही। शेष विभागों की प्रगति सन्तोषजनक रही। जिन विभागों की प्रगति कम एवं शून्य रही उनके प्रति अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित विभागों को इस वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि में आवण्टित लक्ष्यों के विरुद्ध शत-प्रतिशत गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपलब्धि अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिन सूत्रों में बी अथवा सी श्रेणियां हैं उनसे सम्बन्धित विभागों को ए श्रेणी व शत-प्रतिशत उपलब्धि के साथ राज्य स्तर की रैंकिंग में जिला अजमेर अग्रणी जिला बने इस हेतु अभी से कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष के शेष रहे महीनों में शत-प्रतिशत मात्रात्मक गुणात्मक उपलब्धि अर्जित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सभी सम्बंधित विभाग 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक प्रगति सूचनाएं प्रतिमाह 1 तारीख तक जिला योजना प्रकोष्ठ को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। साथ ही मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा विभाग के अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ से ही राज्य सरकार से प्राप्त लक्ष्यानुरूप शत प्रतिशत मात्रात्मक व गुणात्मक उपलब्धि अर्जित किया जाना सुनिश्चित करावें तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनायें जिला स्तर के विभागीय सक्षम अधिकारी से जांच/पुष्टि उपरांत हस्ताक्षरयुक्त मासिक प्रगति सूचना निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख तक व त्रैमासिक प्रगति सूचना आवश्यक रूप से जिला योजना प्रकोष्ठ को प्रेषित करावें, ताकि जिला स्तर से वांछित प्रगति सूचना संकलित तैयार कर निर्धारित समय पर उच्चाधिकारियों व सम्बन्धित विभागों तथा राज्य सरकार को प्रेषित की जा सके।

ग्रामीण सेवा शिविर सरकार आ रही आपके द्वार

-17 से लगेंगे शिविर विभिन्न विभागों की सेवाएं मिलेंगी ग्राम पंचायत स्तर पर

अजमेर (रोयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का उनके घर के पास ही समाधान करने के लिए 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण तुरंत होगा। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितम्बर से आयोजित होंगे। प्रत्येक सप्ताह बुधवार से शनिवार तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाना, किसान गिरदावरी एप्प डाउनलोड करवाना एवं किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित करना। राजस्व न्यायालयों के लम्बित नोटिसों की तामीली, लम्बित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतरण, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाना सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10 हजार और गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे तथा विधायक, सांसद निधि तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल इत्यादि की मरम्मत कार्य संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा मिशन हरियाळो राजस्थान के अंतर्गत वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के आवेदन एवं स्वीकृति जारी करना, अकार्यशील को कार्यशील बनाना, आरआरसी केन्द्रों को भूमि आवंटन एवं स्वीकृति जारी करना स्वामित्व योजना के तहत पट्टों के लिए आवेदन स्वीकृति एवं वितरण और क्षतिग्रस्त स्कूलों आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं सड़कों के सुधार के लिए आपदा प्रबन्धन की गाईड लाईन के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने जैसे कार्य किए जाएंगे। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर स्क्रीनिंग और बच्चों के टीकाकरण, पीएमजेवाए कार्ड बनाए एवं वितरित कराए जाएंगे।

जिला कलक्टर ने चितलवाना उपखंड क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित हुए क्षेत्रों का किया दौरा

-राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

जालोर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे एवं जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया ने गुरुवार को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए चितलवाना उपखंड के सुजानपुरा, हाडेचा, काछेला, खासरवी व चितलवाना ग्रामों सहित नेहड़ क्षेत्र का दौरा किया। जिला कलक्टर ने एनडीआरएफ टीम के साथ नाव एवं ट्रैक्टर के माध्यम से ग्राम सुजानपुरा पहुंचे, वहाँ पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा बारिश के समय आवागमन के लिए पुलिया का निर्माण, जलभराव की स्थिति का स्थाई समाधान सहित विभिन्न मांगे जिला कलक्टर के समक्ष रखी। जिला कलक्टर डॉ प्रदीप के. गावंडे ने ग्रामीणों की समस्त समस्याओं को सुनकर उन्हें आश्वासित किया कि जिला प्रशासन द्वारा इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निस्तारण किया जाएगा। जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए क्षेत्रों में ग्रामीणों हेतु दवाइयां एवं पर्याप्त राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सांचौर दौलताराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर आवड़दान रत्नू, उपखण्ड अधिकारी देशलाराम परिहार, तहसीलदार चितलवाना चमनलाल सियोल, विकास अधिकारी आवड़दान चारण सहित अधिकारी-कार्मिक उपस्थित रहे।

ग्रामीण सेवा शिविर, शहर चलो एवं सहकार सदस्यता अभियान में हाथों हाथ होंगे काम

-अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने हेतु करें बैठक एवं प्रशिक्षण

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। आगामी 15 सितंबर से शुरू होने वाले विभिन्न अभियानों के सुचारू संपादन एवं सफल कार्य आयोजन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं ग्राम स्तर तक के कर्मचारियों की बैठक लेते हुए उन्हें शिविर में संपादित होने वाले कार्यों की पूर्ण जानकारी देते हुए प्रशिक्षित करने तथा जिम्मेदारी पूर्वक कार्य संपादन हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को जिला परिषद की ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शहर चलो अभियान, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर अभियान तथा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सहकारिता सदस्य अभियान के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित शिविर हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, किए जाने वाले कार्य संपादन की पूर्ण कार्य योजना बनाने, प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिस क्षेत्र में शिविर आयोजित होना है वहां पूर्व से ही फ्री कैंप लगाकर चिन्हीकरण करने, प्रतिदिन निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने,अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों के सुचारू संपादन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने स्तर पर अपने विभाग से संबंधित जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए शिविर के उद्देश्य तथा उसमें विभाग से संबंधित होने वाली गतिविधियों के बारे में पूर्ण प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बाड़ी में अटल जन सेवा शिविर आयोजित

धोलपुर (रॉयल पत्रिका)। सरकार की जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने गुरुवार को बाड़ी के पंचायत समिति सभागार में आयोजित अटल जन सेवा शिविर में जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पीड़ित को राहत व संतुष्टि दिलवाना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान सार्वजनिक हित के कई परिवाद प्राप्त हुए जिन पर जिला कलक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समुचित कार्यवाही कर समाधान हेतु निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान आमजन ने अपने मुद्दे और समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखीं। जिला कलेक्टर ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 3 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष प्रकरण सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के लिए प्रेषित किए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक निर्धारित समय-सीमा में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए और लाभार्थियों को वास्तविक राहत आ लाभ मिले। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी शिविर में प्राप्त होने वाले परिवादों का हर संभव समाधान का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि परिवादियों को सही जानकारी देकर सहानुभूति पूर्वक परिवादों का निस्तारण किया जाये। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के उपरांत पंचायत समिति बाड़ी का निरीक्षण किया। विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत समिति परिसर की साफ-सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल के चीफ कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर प्रसाद सैनी नियुक्त

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक होगा। इसमें विश्व के 107 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला खेल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि भारत की ओर से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 73 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें 54 पुरुष और 19 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय टीम के चीफ कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर प्रसाद सैनी रहेंगे। सैनी मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के निवासी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसी बड़ी प्रतियोगिता में चीफ कोच बनने वाले सैनी राजस्थान के प्रथम कोच हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं हितधारकों की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। ज़िला कलक्टर अक्षय गोदारा के निर्देशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद रवि वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई तथा आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने संबंधित विभागों को सतर्कता बरतते हुए सामूहिक एवं समन्वित प्रयासों से बाल विवाह पर रोकथाम के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण स्तर तक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित कर अधिक से अधिक समुदाय को जागरूक करने पर बल दिया। इस दौरान सहायक निदेशक बाल अधिकारिता हुकम चंद जाजोरिया ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में सतर्क रहकर समय पर कार्यवाही करनी होगी तथा विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत रोकथाम सुनिश्चित करनी होगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सामाजिक आंदोलन के रूप में लिया जाना चाहिए। परिवारों को समझाना, बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना और समुदाय को मानसिकता बदलने के लिए प्रेरित करना सभी हितधारकों का साझा दायित्व हैं। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता भैरू प्रकाश नागर ने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग निरंतर बाल विवाह उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाएँ और किशोरियों को शिक्षा एवं कौशल से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दें।

तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत सागवाड़ा बार ऐसोसिएशन के साथ किया बैठक का आयोजन

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकृति के विवादों के निस्तारण के लिए वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को किया जाना है। जिसके संदर्भ में 10 सितम्बर 2025 को सुनील कुमार पंचोली, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर की निर्देशानुसार मनोज मीना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा तालुका मुख्यालय सागवाड़ा के न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन, बार सभागार सागवाड़ा में किया गया। बैठक में पूनाराम गोदार, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सागवाड़ा एवं हरिश मेनारिया अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा तथा हरिश पाटीदार, अध्यक्ष बार ऐसोसिएशन, सागवाड़ा, भरत खराडी सचिव, बार ऐसोसिएशन, सागवाड़ा वरिष्ठ अधिवक्तागण विजयकुमार जैन, आजाद शाह, अनिरूद्ध सिंह चुण्ड़ावत, मुनीर शहजाद, लालाशंकर पाटीदार शेलेन्द्र जैन एवं अन्य अधिवक्तागण, उपस्थित हुवे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा उपस्थित अधिकारीगण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित न्यायालयों के राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करने का एवं अधिवक्तागण को सहयोग करने का आह्वान किया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा मिडियेशन-फोर द नेशन केम्पेन हेतु भी अधिकारीगण से चर्चा की गयी जिसमें अधिकारीगण को अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता वार्ता करायी जाकर प्रकरण को निपटाया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में रेफर कर इस केम्पेन के माध्यम से निपटाने का प्रयास किये जाने पर जोर दिया।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

-10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां

धोलपुर (रॉयल पत्रिका)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारियों से बचाव एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा के निर्देशन में आत्महत्या के प्रयासों को कम करने एवं आमजन को जागरुक करने के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतराम मीणा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के जिला नोडल अधिकारी डॉ. सुमित मित्तल सहित ने मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम हेतु किए जाने वाले प्रयासों के बारे में चर्चा की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतराम मीणा ने कहा कि बढ़ते आत्महत्या के मामले, वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय हैं। हर साल दुनियाभर में लाखों लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाते हैं। भारत में भी ये समस्या बड़ी चिंता बनकर उभर रही है। भारत में छात्र वर्ग एवं लोगों में आत्महत्या की वार्षिक दर तेजी से बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते आत्महत्या की रोकथाम के लिए योजना बनाने, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्महत्याओं को रोकने के प्रयास को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है।

सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4एमएल में नशा विरोधी कार्यशाला

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर डॉ. मंजू एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के नेतृत्व में जारी नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4एमएल में नशा विरोधी कार्यशाला आयोजित हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विक्रम ज्याणी ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि नशा सपनों को जलाने वाला धुआं है, अपनों की आँखों का आंसू मत बनो और नशा छोड़कर जिंदगी चुनो, खुद की ताक़त बनो, दूसरों का सहारा बनो। नशा आपकी उम्र के कई बच्चों का भविष्य छीन चुका है। कहानियों और उदाहरणों के ज़रिये समझाया कि नशा क्यों खतरनाक है और क्यों हमें इससे हमेशा दूर रहना है। जिम्मेदारी और सपनों वाली सोच रखोगे, तो नशा आपको कभी पकड़ नहीं सकता। एक छोटी गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। नशा शुरू में शौक लगता है, बाद में शोक बन जाता है। जिम्मेदार लोग ही समाज का भविष्य बदलते हैं। आप सबको जिम्मेदारी लेनी है, नशा नहीं करना है और अपने दोस्तों को भी रोकना है। प्रधानाचार्य विनय गुप्ता ने कहा कि अंधेरों से लड़ना है, तो रोशनी बनो। कमजोरियों से बचना है, तो जिम्मेदार बनो। नशा छोड़कर ज्ञान चुनो और अपने सपनों का भविष्य चुनो। कार्यशाला में सभी ने मिलकर सामूहिक शपथ लेते हुए कहा कि हम सब मिलकर कसम खाते हैं, नशे से हमेशा दूर रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय के अध्यापकगणों सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।

महिला अधिकारिता विभाग पोक्सो एक्ट की कार्यशाला का आयोजन

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। महिला अधिकारिता द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के मिशन शक्ति अभियान अन्तर्गत संकल्प- हब फॉर एंपावरमेट ऑफ वूमेन के विशेष जागरूकता अभियान के अन्तर्गत सहकार भवन के सभागार में पोक्सो एक्ट की कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक मेघा रतन ने कहा कि समाज के बदलते परिवेश में इस बात की अवधारणा ओर अधिक बढ़ जाती है कि बालक हमारी मानवीय पूंजी है, इसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखना हमारा सामाजिक दायित्व व नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार मिशन शक्ति योजना संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन के तहत 2 सितम्बर से दस दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान जो कि 12 सितम्बर तक संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर पर पोक्सो एक्ट की कार्यशाला का यह आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जिला स्तर पर ही नहीं अपितु विभाग के पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता के द्वारा भी ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें ग्राम साथिन सहित स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण सहभागिता कर रहे है। उन्होने पोक्सो एक्ट के विषय में उपस्थित संभागीगणों को सम्बोधित करते हुये कहा कि कार्यशालाओ की महत्वता तब सार्थक होगी जब हम इसे फिल्ड एवं अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कार्यान्वित करावें। इससे पूर्व उन्होंने विशेष जागरूकता कार्यक्रम के विषय में विस्तार से अवगत करवाते हुये कहा कि यह कार्यक्रम 2 सितम्बर से संचालित है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में आवेदन 14 सितम्बर तक करें

धोलपुर (रॉयल पत्रिका)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब तकरीबन 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितम्बर निर्धारित की गई है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं और विभिन्न सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाएगी। इसमें यूपीएससी, आरपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा, रीट, कांस्टेबल भर्ती, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, क्लैट, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सीएम अनुप्रति योजना आइकन पर क्लिक करें और स्टूडेंट विकल्प से आवेदन करें। योजना का लाभ वही अभ्यर्थी ले सकेंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपये तक हो। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी किसी शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कार्मिक के रूप में कार्यरत है तो वह पात्र नहीं होगा।

वायरल हो गया वीडियो

'जॉली एलएलबी 3' के ट्रेलर लॉन्च पर अक्षय-अरशद की हरकत

'जॉली एलएलबी 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के कई वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का आज ट्रेलर सामने आया है। इस कोर्ट रूम कॉमेडी-ड्रामा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कानपुर और मेरठ में रखा गया। यहां अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा फिल्म की बाकी कास्ट में सौरभ शुक्ला भी नजर आए। अब ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम से जुड़े कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

अक्षय-अरशद ने चूमा जज त्रिपाठी का सिर

एक वीडियो वायरल है जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ फिल्म में जज त्रिपाठी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सौरभ शुक्ला भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में अरशद और अक्षय सौरभ शुक्ला के सिर पर मस्ती में चूमते नजर आ रहे हैं।

दिव्या खोसला कुमार की एक चतुर नार रिलीज के लिए तैयार

बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता दिव्या खोसला कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म एक चतुर नार की रिलीज को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिव्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के सेट से एक बीटीएस वीडियो पोस्ट किया। इस बिहाइंड द सीन (बीटीएस) वीडियो में दिव्या एक सीन करती नजर आ रही हैं। उनकी तारीफ सेट पर मौजूद सिनेमैटोग्राफर समीर आर्यन और नील नितिन मुकेश कर रहे हैं। वहीं, दिव्या अपने किरदार के अनुरूप पारंपरिक लुक में दिख रही हैं। उन्होंने बैंगनी रंग का कुर्ता, पीली सलवार और स्लेटी रंग का स्वेटर पहना है, जिसके ऊपर चुन्नी भी है। बालों में बनाई गई चोटी उनके चतुर नार वाले किरदार को जीवंत कर रही है। इस लुक ने दर्शकों को उनके किरदार के प्रति और उत्सुक कर दिया है। दिव्या ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, एक चतुर नार के सेट से खास पल। हमारे टैलेंटेड डीओपी समीर आर्यन और मुझे बेहद खूबसूरती से नील नितिन मुकेश ने कैमरे में कैद किया। ये मेरी सबसे पसंदीदा और शानदार टीम है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म एक चतुर नार में दिव्या का देसी और दमदार अवतार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए तैयार है। उनके इस लुक और बीटीएस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तारीफों का सिलसिला शुरू कर दिया है। फैंस अब बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की कहानी एक छोटे शहर में रहने वाली होनहार लड़की की है। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और चालाक है। एक दिन उसके हाथ बड़े शख्स का प्राइवेट वीडियो आ जाता है।

विद्युत जामवाल का पोटेंशियल यूज करने में फेल रहा बॉलीवुड

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी हालिया फिल्म दिल मद्रासी की बॉक्स ऑफिस सफलता का जश्न मना रहे हैं। विद्युत जल्द ही हॉलीवुड की स्ट्रीट फाइटर के नए लाइव-एक्शन अडैप्शन में भी नजर आएंगे। फैन्स ने बॉलीवुड पर इनके सही इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया है।

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल अपनी हालिया तमिल फिल्म दिल मद्रासी की बॉक्स ऑफिस सफलता का जश्न मना रहे हैं। इस एक्शन थ्रिलर में शिवकार्तिकेयन लीड रोल में हैं और विद्युत विलन की भूमिका निभा रहे हैं।इस फिल्म से कई वर्षों के बाद साउथ सिनेमा में उनकी वापसी हुई है। विद्युत हॉलीवुड की स्ट्रीट फाइटर के नए लाइव-एक्शन अडैप्शन में भी नजर आएंगे। इस बीच, एक्टर के फैन्स ने बॉलीवुड पर उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया है और इससे विद्युत भी सहमत नजर आ रहे हैं। विद्युत ने फैन्स की बॉलीवुड की आलोचना को फिर से शेयर किया है। स्ट्रीट फाइटर की घोषणा के बाद, विद्युत के कई फैन्स ने उनकी लेटेस्ट फिल्म मद्रासी से उनकी कुछ झलकियां शेयर कीं। उन्होंने उनके लुक की भी जमकर तारीफ की। इंस्टाग्राम पर एक मीम में विद्युत का मद्रासी फिल्म से लुक दिखाया गया था, जिसके साथ कैप्शन लिखा था, बॉलीवुड इस आदमी की क्षमता का उपयोग करने में विफल रहा। इसी तरह, ट्विटर पर एक विदेशी फैन ने विद्युत के लुक की तारीफ करते हुए कहा, लाइव-एक्शन स्ट्रीट फाइटर में धालसिम का किरदार निभाने वाले एक्टर बहुत ही हैंडसम है। एक इंडियन फैन ने ट्वीट पर रिएक्शन देकर कहा, काश भारतीय फिल्म जगत को अपने असली क्षमता का पता होता, लेकिन इसके बजाय वे साल-दर-साल मिड सीजन फिल्में बना रहे हैं।

दिल मद्रासी ने पांच दिनों में की शानदार कमाई

विद्युत ने इन दोनों पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट किया है। एआर मुरुगादॉस निर्देशित मद्रासी बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल मद्रासी ने पांच दिनों में भारत में 44.45 करोड़ रुपये की कमाई की और वर्ल्डवाइड 71 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। इस फिल्म की कहानी और कलाकारों की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है।

'सन ऑफ सरदार 2' में खुद को दरकिनार किए जाने पर सोनाक्षी ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सन ऑफ सरदार फिल्म का हिस्सा थीं, जिन्हें दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। हालांकि उन्हें सन ऑफ सरदार 2 में मेकर्स ने जगह नहीं दी। उनकी जगह फिल्म में मृणाल ठाकर ने मुख्य भूमिका निभाई। अब सोनाक्षी ने आखिरकार अजय देवगन अभिनीत इस फिल्म के दूसरे भाग में अपनी अनुपस्थिति पर सफाई दी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है कारण।

क्या बोलीं सोनाक्षी सिन्हा?

सोनाक्षी सिन्हा ने बातचीत में सन ऑफ सरदार 2 में हिस्सा ना होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'जहां तक मैं देख सकती हूं कि सन ऑफ सरदार 2 फिल्म के लिए वे विदेश गए थे। इसलिए वही किरदार कहानी का हिस्सा नहीं हो सकता था। आप केवल इसके लिए अपमानित महसूस नहीं कर सकते। आपको व्यावहारिक होना होगा और प्रत्येक फिल्म को एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में लेना होगा।'

सन ऑफ सरदार 2 के बारे में

सन ऑफ सरदार 2 फिल्म में अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकर मुख्य भूमिका में थीं। इस फिल्म को विजय कुमार अरोड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था। वही इस कॉमेडी ड्रामा में रवि किशन, विंदू दारा सिंह और संजय मिश्रा जैसे कलाकार भी मौजूद थे।

सोनाक्षी सिन्हा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म जटाधारा है। इस फिल्म से सोनाक्षी सिन्हा का लुक भी सामने आ चुका है, जो उनके फैन्स को काफी पसंद भी आया। फिल्म में एक्ट्रेस के साथ साउथ एक्टर सुधीर बाबू लीड रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा सोनाक्षी को आखिरी बार निकिता रॉय में देखा गया था। इस फिल्म को कुश सिन्हा द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में सोनाक्षी ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी, जो टूटी हुई भी है, जिद्दी भी और कहीं न कहीं अपनी ही सोच में खोई हुई है।

अक्षरा सिंह ने जिंदगी के नाम दिया बड़ा संदेश

अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, जिसने न सिर्फ उनके फैंस का दिल छू लिया, बल्कि उनके कैप्शन ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस पोस्ट में अक्षरा ने कैप्शन में अपने जज्बात लिखे। तस्वीर में अक्षरा सिंह एक खूबसूरत सूट में नजर आ रही हैं जो उनकी सादगी और खूबसूरती को और निखार रहा है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग चमक है। अपने जज्बातों को जाहिर करते हुए अक्षरा ने लिखा, हो अगर गलतफहमियां, तो भी खामोशी से मुस्कुराऊंगी, शिकवे नहीं, बस सब्र से अपने जज्बातों को छुपाऊंगी। इस कैप्शन में अक्षरा ने न सिर्फ अपने जज्बात जाहिर किए हैं, बल्कि एक संदेश भी दिया है कि चाहे हालात कैसे भी हों, खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, साथ न दो तुम अगर, तो भी न डगमगाऊंगी, कांटों की राहों पर चलकर भी, अपने हौसलों को सजाऊंगी। दिल टूटे तो क्या हुआ, सांसों का सफर अब भी बाकी है, जिंदगी की किताब में कुछ नए पन्ने लिखने की झांकी है, हर दर्द को रोशनी में बदलकर खुद को ही अपनाऊंगी, हो अगर गलतफहमियां, तो भी खामोशी से मुस्कुराऊंगी।

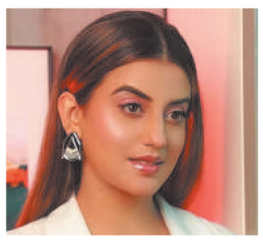

माही विज का ट्रेडिशनल लुक

मशहूर टीवी अभिनेत्री माही विज को लागी तुझसे लगन, बालिका वधू, अकेला, कैसी लगी लगन, और शुभ कदम जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में देखा गया है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में अभिनेत्री अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह कैमरे की ओर देखकर अपनी मुस्कान बिखेरती हैं, तो कभी फूलों के साथ खेलते हुए आकर्षक अंदाज में पोज देती हैं। उनकी यह सहजता और खूबसूरती प्रशंसकों को खूब भा रही है। माही ने इस वीडियो में हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना है, जो उनकी सादगी और शालीनता को और निखार रहा है। हल्के मेकअप के साथ उन्होंने बड़े-बड़े झुमके पहने हैं, जो उनके लुक को और आकर्षक बना रहे हैं। उनके बालों को हल्का कर्ल किया गया है और कानों के पीछे हल्के गुलाबी रंग का गुलाब सजाया गया है, जो उनके इस पारंपरिक लुक को और खास बना रहा है।

रीम का स्टाइलिश अंदाज

टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रीम शेख अपने खूबसूरत लुक और अनोखे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ वह फैशन के मामले में भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं। बुधवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में रीम ने काले रंग का लखनऊ चिकनकारी अनारकली सूट पहना है, जो उनकी सादगी और स्टाइल का शानदार मिश्रण पेश करता है। इस सूट की बारीक कढ़ाई और हल्का-फुल्का फैब्रिक उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है। रीम ने अपने इस ट्रेडिशनल परिधान को सादगी भरे मेकअप के साथ पूरा किया। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ रखा है, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखार रहा है। इसके साथ ही रीम ने सफेद रंग के बड़े-बड़े झुमके पहने, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं। तस्वीरों में वह अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आईं, जिसमें उनकी मुस्कान और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। हर तस्वीर में उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास फैंस को लुभा रहा है।

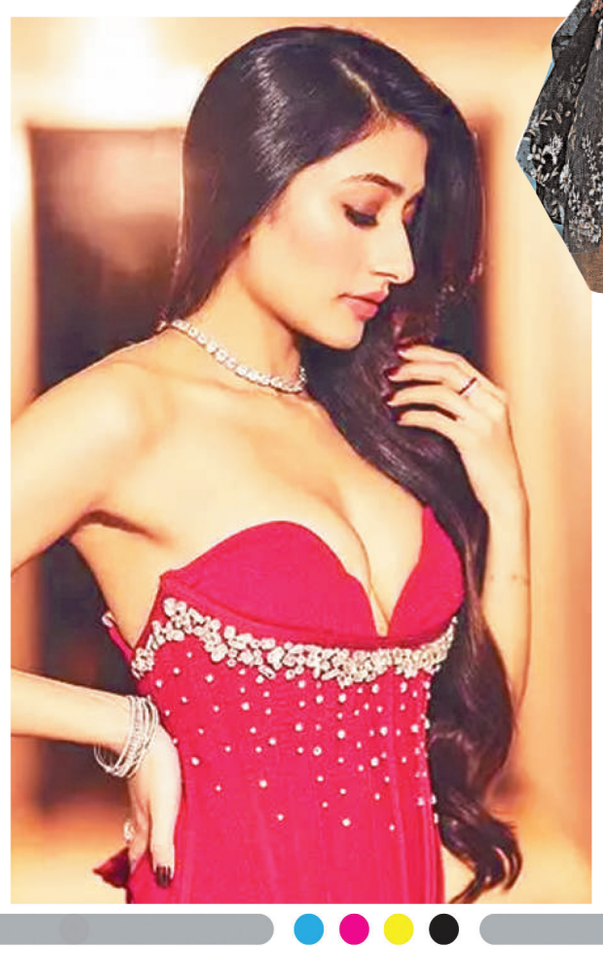

युजवेंद्र चहल से तलाक नहीं, टैलेंट की वजह से मिल रहे हैं फिल्मों के ऑफर: धनश्री

कोरियोग्राफर और अभिनेत्री इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं। उन्हें इस शो के अलावा भी कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इसकी वजह युजवेंद्र चहल से उनका तलाक है, वह इसके लिए खूब सुर्खियों में रहीं। धनश्री वर्मा तलाक से मिली लोकप्रियता को भुना रही है, इस पर अब उनका रिएक्शन सामने आया है। धनश्री वर्मा ने बताया कि फिल्मों के ढेर सारे ऑफर मिलना तलाक की वजह से नहीं, बल्कि उनका टैलेंट है। धनश्री वर्मा ने कहा, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। मैं यहां अकेले खड़ी हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे काम मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इंडस्ट्री से प्यार है, क्योंकि लोग अब भी मुझे काम दे रहे हैं। मुझे ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझमें टैलेंट है। इसका किसी और चीज से कोई लेना-देना नहीं है।

साभार एजेंसी

कुलदीप यादव अब शायद अगला मैच न खेलें: मांजरेकर ने इशारों में गौतम गंभीर की आलोचना की

नई दिल्ली, एजेंसी। कुलदीप यादव ने दुबई में भारत के लिए एशिया कप अभियान की शानदार शुरुआत की और श्व के खिलाफ केवल 4.3 ओवर में 57 रनों पर ढेर करके रिकॉर्ड तोड़ जीत में मदद की। शुरुआत से ही भारतीय टीम का दबदबा रहा,

क्योंकि जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन यॉर्कर ने शुरुआत की - लेकिन कुलदीप द्वारा फेंके गए 9वें ओवर में बाएं हाथ के इस लेग स्पिनर ने तीन विकेट लिए, UAE के बल्लेबाजों को धूल चटाई और 7 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। इंग्लैंड में भारत के सभी 5 टेस्ट मैचों में बेंच पर बैठने के बाद टीम में वापसी करने वाले इस खिलाड़ी ने तुरंत ही अपनी छाप छोड़ी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से अपना हुनर ??दिखाने के लिए बेताब था। कुलदीप के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी, उन्हें अक्सर टीम में अंदर-बाहर होते देखा गया है, और संजय मांजरेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जाहिर कर दिया कि कुलदीप की भागीदारी और समावेशन को जिस तरह से संभाला गया है, उससे वे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। मांजरेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए कहा, कुलदीप ने एक ओवर में 3 विकेट लिए। अब शायद अगला मैच न खेलें। उन्होंने एक मजाकिया इमोजी भी लगाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी टिप्पणी को सही अर्थ में लिया जाए। कुलदीप टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों में भारत की जीत का अहम हिस्सा रहे थे। कई लोगों का मानना है कि उन्हें टेस्ट सीजन में टीम का हिस्सा होना चाहिए था, खासकर जब गौतम गंभीर को नतीजे हासिल करने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि इस लेग स्पिनर को एक ऐसे देश में एक विशुद्ध स्पिनर होने का दुर्भाग्य मिला है जहां कई स्पिन गेंदबाज हैं जो बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें रवींद्र जडेजा और हाल ही में वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा है।

शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन का किया खुलासा, कहा- गेंदबाजी कोच ने मुझे कुछ विशेष सलाह दी है

दुबई, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग में इंपैक्ट प्लेयर नियम के कारण शिवम दुबे की गेंदबाजी में भूमिका सीमित हो गई थी लेकिन वह भारतीय टीम के लिए अदद ऑलराउंडर बनना चाहते हैं जिसमें उन्हें मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का मार्गदर्शन मिल रहा

है। संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट लेने वाले दुबे ने एक तेज गेंदबाज के रूप ने अपने खेल में सुधार के संबंध में मोर्कल की भूमिका के बारे में बात की। दुबे ने भारत की 9 विकेट से जीत के बाद कहा, 'जब से मैं इंग्लैंड श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में वापस आया हूं, तब से मोर्ने मेरे साथ काम कर रहे हैं।

उन्होंने मुझे कुछ विशेष सलाह दी है और मैंने उन पर अमल किया है। इस विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा, 'उन्होंने मुझे ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की लाइन पर गेंदबाजी करने को कहा। उन्होंने धीमी गेंद करने को लेकर भी मेरे साथ काम किया और मेरे रन-अप में भी थोड़ा बदलाव किया। मुख्य कोच और कप्तान ने मुझे बताया था कि मेरी गेंदबाजी की भूमिका अहम होगी। आईपीएल के बाद दुबे को अपने ऑलराउंड खेल और फिटनेस पर काम करने के लिए दो महीने का समय मिला। दुबे का आईपीएल में उनकी फ्रैंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स पावर-हिटर के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करती है। दुबे ने कहा, 'पिछले दो महीनों में, मैंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। जहां तक मेरी बल्लेबाजी का सवाल है तो मुझे पता है कि बीच के ओवरों में मुझे (एक पावर-हिटर के तौर पर) अपनी भूमिका निभानी है।

ऐतिहासिक फैसला:

महिला वनडे विश्व कप में अंपायर और रेफरी सिर्फ महिलाएं

दुबई, एजेंसी। महिला वनडे विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में विश्व कप को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। महिला वनडे विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट की सारी मैच ऑफिशियल्स और अंपायर महिलाएं होंगी।

इससे पहले 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में मैच ऑफिशियल्स और अंपायर के रूप में महिलाएं दिख चुकी हैं। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, यह महिला क्रिकेट के सफर में एक निर्णायक क्षण है। हमें उम्मीद है कि यह खेल के सभी पहलुओं में कई और नई कहानियों का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैच अधिकारियों के रूप में महिला पैनल का शामिल होना न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि क्रिकेट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी की अटूट प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतिबिंब भी है। उन्होंने कहा, यह विकास प्रतीकात्मक मूल्य से कहीं आगे जाता है। यह दृश्यता, अवसर और ऐसे सार्थक रोल मॉडल के निर्माण के बारे में है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को उजागर करके, हमारा उद्देश्य आकांक्षाओं को जगाना और इस बात को पुष्ट करना है कि क्रिकेट में नेतृत्व और प्रभाव लिंग-भेद से परे है।

शाह ने कहा, महिलाओं के खेल के विकास में एक नए अध्याय को मान्यता देते हुए हमें गर्व हो रहा है। हमारा मानना है कि इस पहल का प्रभाव इस टूर्नामेंट से कहीं आगे तक जाएगा, जिससे दुनिया भर में अधिकाधिक महिलाओं को अंपायरिंग करियर अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और खेल के भीतर क्या संभव है, इसे पुनः परिभाषित करने में मदद मिलेगी। आईसीसी द्वारा घोषित अंपायर्स और रेफरियों के पैनल में तीन भारतीय नाम भी शामिल हैं। जीएस लक्ष्मी रेफरी होंगी जबकि वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन अंपायर होंगी।

वर्ल्डबॉक्सिंग चैंपियनशिप:

नूपुर-पूजा ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक पक्का किया, निकहत बाहर

लिवरपूल, एजेंसी। महान मुक्केबाज हवा सिंह की पोती नूपुर ने चैंपियनशिप के अपने पहले मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंद्वी को 4-1 से हराकर 80 किग्रा से अधिक वर्ग के अंतिम चार में प्रवेश किया। भारत की अनुभवी मुक्केबाज पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोटेरस्का को हराकर महिलाओं के 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और इस तरह से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना पहला पदक पक्का किया। इस तरह से विश्व चैंपियनशिप में भारत के तीन पदक पक्के हो गए हैं। पूजा से पहले दो बार की एशियाई चैंपियन जैस्मीन लेम्बोरिया (57 किग्रा) और नुपुर शेरॉन (80 किग्रा से अधिक) ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए थे।

पहले दौर में बाई हासिल करने वाली 34 वर्षीय पूजा ने अपने अनुभव के दम पर बुधवार देर रात क्वार्टर फाइनल में कोटेरस्का को 3-2 से हराया। 80 किग्रा भार वर्ग ओलंपिक में शामिल नहीं है और विश्व चैंपियनशिप में इस वजन वर्ग में 12 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। इस बीच भारत के पुरुष मुक्केबाजों के अभियान को एक और झटका लगा जब अभिनाश जामवाल 65 किग्रा क्वार्टर फाइनल में जॉर्जिया के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लाशा गुरुली से 1-4 के विभाजित निर्णय से हार गए। उनके बाहर होने के बाद पुरुष वर्ग में केवल जदुमणि सिंह (50 किग्रा) ही दौड़ में बचे हैं। अंतिम आठ में उनका सामना मौजूदा विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के संझार ताशकेनबे से होगा। इस तरह से भारतीय पुरुष मुक्केबाजों का ताशकंद में खेली गई पिछली विश्व चैंपियनशिप की तुलना में यहां प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पिछली प्रतियोगिता में दीपक भोरिया (51 किग्रा), मोहम्मद हुसामुद्दीन (57 किग्रा) और निशांत देव (71 किग्रा) ने कांस्य पदक जीते थे। महिलाओं की पिछली प्रतियोगिता नयी दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें नीतू घंघास (48 किग्रा), निकहत (50 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) और स्वीटी बूरा (81 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते थे।

पूजा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले राउंड में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन पोलैंड की खिलाड़ी ने पलटवार करते हुए यह राउंड 3-2 से जीत लिया। एशियाई खेल 2014 की कांस्य पदक विजेता पूजा ने दूसरे राउंड में अच्छी वापसी करके बड़ी बढ़त हासिल की। तीसरे राउंड तक दोनों मुक्केबाज थक चुकी थीं, लेकिन पूजा ने धैर्य बनाए रखा और आखिर में अपने नाम पर पदक पक्का किया।

स्पेनिश लीग मैच में एमबाप्पे का अपमान करने वाले शख्स पर हुई कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि लीग की आधिकारिक शिकायत के बाद की गई जांच में आरोपी की पहचान की गई और उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी पर आरोप है कि उसने मैच के दौरान एमबाप्पे की ओर बंदर जैसी हरकतें और आवाजें निकालीं। स्पेनिश पुलिस ने एक दर्शक को गिरफ्तार किया है, जिस पर रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी कायलियन एमबाप्पे के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप है। यह घटना पिछले महीने स्पेनिश लीग के एक मुकाबले में हुई थी। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि लीग की आधिकारिक शिकायत के बाद की गई जांच में आरोपी की पहचान की गई और उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी पर आरोप है कि उसने मैच के दौरान एमबाप्पे की ओर बंदर जैसी हरकतें और आवाजें निकालीं।

हाल के वर्षों में लगातार आ रहीं घटनाएं

यह घटना 24 अगस्त को रियल मैड्रिड और ओवीएदो के बीच खेले गए मुकाबले के पहले हाफ के दौरान घटी थी। उसी समय एमबाप्पे ने मैच का पहला गोल किया था और मैड्रिड ने मुकाबला 3-0 से जीता था। स्पेनिश फुटबॉल में हाल के वर्षों में अश्वेत खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लभेदी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले हफ्ते, एस्पान्योल क्लब के एक प्रशंसक ने एथलेटिक बिलबाओ के फॉरवर्ड इनियाकी विलियम्स का पांच साल पहले किया गया नस्लीय अपमान स्वीकार किया था और जेल की सजा से बचने के लिए समझौता कर लिया था।

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैच शुड गो ऑन

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जारी रहना चाहिए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जनहित याचिका (पीआईएल) में दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मैच रविवार को होने वाला है, इसलिए शुक्रवार को ही इस मामले की सुनवाई कर ली जाए। याचिका में दावा किया गया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय गरिमा और शहीदों के सम्मान के खिलाफ है। यह याचिका चार लॉ स्टूडेंट्स की ओर से दायर की गई, जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 को लागू करने की भी मांग की। यह याचिका अधिवक्ता स्नेहा रानी, ??अभिषेक वर्मा और मोहम्मद अनस चौधरी के माध्यम से दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई वाली बेंच ने गुरुवार को इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि यह एक मैच है और इसे जारी रहने देना चाहिए। एशिया कप में भारत ने यूएई के खिलाफ रिकॉर्ड जीत के साथ आगाज किया है। अगला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। यह मैच 14 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हराया। पहले गेंदबाजी करते हुए, भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले को एकतरफा बनाया और यूएई को 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर ढेर कर दिया। स्पिनरों और ऑलराउंडरों के लिए यह एक यादगार रात थी। कुलदीप यादव गेंदबाजी में स्टार रहे, उन्होंने सिर्फ 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट लिया। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शुरुआत में ही दबाव बनाए रखते हुए लय हासिल की। यूएई का बल्लेबाजी क्रम उनकी लगातार सटीकता के आगे लड़खड़ा गया, जिसमें सिर्फ अलीशान शराफू के 17 गेंदों में 22 रन ही रहे। 58 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के शीर्ष क्रम ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 30 रनों की तेज पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने सिर्फ 9 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दो बड़े शॉट लगाकर टीम को जीत दिलाई और 13.33 की तेज रन रेट से भारत को सिर्फ 4.3 ओवर में जीत दिला दी।

सात्विक-चिराग की जोड़ी का हांगकांग ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी, क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली, एजेंसी। हांगकांग ओपन 2025 में भारत की सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग

शेट्टी की पुरुष जोड़ी राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का कर लिया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी का सामना राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड की जोड़ी पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल से था जिसमें करीब डेढ़ घंटे तक चले इस मैच में कुल तीन सेट का मुकाबला हुआ जिसे भारतीय मेंस जोड़ी ने 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर के लिए अपनी जगह को पक्का कर लिया। पहले सेट में मिली हार, अगले 2 सेट में दिखाया शानदार खेल वर्ल्ड नंबर 9 रैंकिंग जोड़ी सात्विक और चिराग को राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड के खिलाफ मैच में पहले सेट में 18-21 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दूसरे सेट में सात्विक और चिराग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21-15 उसे अपने नाम करने के साथ मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। तीसरे सेट में सात्विक और चिराग ने काफी आक्रामक खेल दिखाया जिसमें उनके स्मैश और तेज रिफ्लेक्सेस का जवाब थाईलैंड की जोड़ी पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल के पास नहीं था और उन्हें निर्णायक सेट में 21-11 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले सात्विक और चिराग की जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में ताइवान की जोड़ी के खिलाफ भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था जिसमें उन्होंने पहला सेट तो 21-13 के अंतर से जीता लेकिन दूसरे सेट में 18-21 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तीसरे सेट को 21-10 के अंतर से जीतकर वह राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में कामयाब हुए थे।

अब इस देश में होगा रेसलमेनिया, लिक हो गई प्रेस रिलीज

नई दिल्ली, एजेंसी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा इवेंट रेसलमेनिया 43 सऊदी अरब में होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब रेसलमेनिया का आयोजन उत्तरी अमेरिका के बाहर किया जाएगा। यह खबर तब सामने आई जब एक प्रेस रिलीज गलती से लीक हो गई थी, जिसे बाद में तुरंत हटा लिया गया।

प्रेस रिलीज का लीक से मचा बवाल

रिपोर्ट के अनुसार अरबी भाषा में लिखी गई यह प्रेस रिलीज गलती से जारी हो गई थी, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि यह खबर 100 सच है। माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा। इस खबर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। इस घोषणा के साथ यह भी खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब 2026 में रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट की भी मेजबानी करेगा, जो सऊदी अरब में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट होगा।

डब्ल्यूडब्ल्यूई -सऊदी अरब साझेदारी का विस्तार

रेसलमेनिया का यह 43वां सीजन होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि रेसलमेनिया 42 लास वेगास, नेवादा के एलीगेंट स्टेडियम में 2026 में होगा। यह लगातार दूसरा साल होगा जब यह स्टेडियम रेसलमेनिया की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिश्ता 2018 में शुरू हुई 10 साल की साझेदारी का हिस्सा है।

रोनाल्डो से प्रेरणा लेते हैं एशिया कप हॉकी के स्टार अभिषेक, अब है विश्व कप जीतने का सपना

नई दिल्ली, एजेंसी। अभिषेक ने बताया कि भारतीय हॉकी के दिग्गज सरदार सिंह को देखकर ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। हालांकि जब तक अभिषेक टीम में आए, तब तक सरदार सिंह रिटायर हो चुके थे। भारतीय हॉकी टीम के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी अभिषेक ने हाल ही में हुए एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर न केवल खिताब जीता, बल्कि 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इस टूर्नामेंट में अभिषेक ने छह गोल किए और कई मौकों पर गोल बनाने में सहायक रहे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

मुझे रोनाल्डो से मिलती है प्रेरणा

अभिषेक ने बताया कि उनके शुरुआती कोच शमशेर दहिया, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के फैन हैं और चाहते थे कि अभिषेक वैसा ही खेले। लेकिन अभिषेक ने हमेशा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आदर्श माना। उन्होंने कहा, मैं रोनाल्डो के मैच देखता हूं और उनसे स्कोरिंग, पोजिशनिंग, टाइमिंग और शूटिंग के बारे में सीखता हूं। फुटबॉल और हॉकी दोनों ही टीम गेम हैं, और रनिंग और स्टैमिना का अहम रोल होता है। रोनाल्डो मेरी प्रेरणा हैं।

सरदार को देखकर शुरू हुआ हॉकी का सफर

अभिषेक ने बताया कि भारतीय हॉकी के दिग्गज सरदार सिंह को देखकर ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। हालांकि जब तक अभिषेक टीम में आए, तब तक सरदार सिंह रिटायर हो चुके थे। अपने भाई आशीष और एक दोस्त को देखकर उन्होंने पहली बार हॉकी स्टिक थामी थी। बचपन में एक बार कलाई में चोट लगने के कारण माता-पिता ने हॉकी खेलने से मना कर दिया था, लेकिन उनके कोच ने उन्हें दोबारा मैदान पर लाने में मदद की। अभिषेक आज भी अपने पहले कोच, जो हिंदी शिक्षक भी थे, से सलाह लेते हैं। उन्होंने कहा, शमशेर सर को भले ही आधुनिक हॉकी की ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन वह मेरे खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं।

अगला लक्ष्य: विश्व कप और ओलंपिक में पदक

पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक और हांगझोउ एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले इस खिलाड़ी का अगला सपना है विश्व कप जीतना। उन्होंने कहा, हमने 50 वर्षों से विश्व कप नहीं जीता। मुझे लगता है कि हमारी टीम में वो काबिलियत है। हमें सिर्फ निरंतरता और फिनिशिंग पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी को फिर से स्वर्णिम दौर में ले जाने के लिए टीम को जीतने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि अब ओलंपिक में सिर्फ कांस्य नहीं, सोने का पदक चाहिए।

सीपी राधाकृष्णन ने ली भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ

-राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक रहेगा

नई दिल्ली । भारत ने एक बार फिर लोकतंत्र की शक्ति और परंपरा का अद्‌त उदाहरण पेश किया है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन (सीपी राधाकृष्णन) ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और अनेक गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू ने भी समारोह में शिरकत की।

राधाकृष्णन का कार्यकाल और जिम्मेदारी

राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति पद को गरिमा और निष्पक्षता के साथ निभाना होगी। यह पद न केवल संसदीय मर्यादा का प्रतीक है, बल्कि लोकतांत्रिक बहस और निर्णय प्रक्रिया को संतुलित रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। राधाकृष्णन लंबे समय से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें संगठन में मजबूत पकड़ और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया।

चुनावी जीत

9 सितंबर को हुए चुनाव में राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। इस तरह राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत न केवल एनडीए की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि संसद में उनकी स्वीकार्यता और समर्थन का भी संकेत देती है।

इस्तीफे के बाद दिखे जगदीप धनखड़

इस समारोह की एक और खास बात रही कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे को 53 दिन हो चुके थे और इस बीच वे सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए थे। समारोह में उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। धनखड़ ने अपने कार्यकाल में राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने और संसदीय परंपराओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार बहस भी हुई, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखी।

राजनीतिक और सामाजिक महत्व

सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना दक्षिण भारत के लिए भी एक अहम क्षण माना जा रहा है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन का चयन यह संदेश देता है कि केंद्र सरकार और एनडीए दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जड़ें और मजबूत करने की दिशा में गंभीर है। उनकी जीत से यह उम्मीद भी बंधती है कि राज्यसभा में बहसें और चर्चाएं अधिक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में होंगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि उनका अनुभव और विनम्रता राज्यसभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मोदी ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन का सार्वजनिक जीवन स्वच्छ, पारदर्शी और समाज सेवा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। ऐसे में देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन लोकतंत्र के लिए एक नया अध्याय है। उनका कार्यकाल न केवल संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर होगा, बल्कि देश की एकता और विविधता को मजबूती देने का भी समय होगा। जैसे-जैसे वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, देश यह देखेगा कि कैसे एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक का सफर तय करने वाला व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र की सच्ची ताकत को दर्शाता है। राधाकृष्णन का कार्यकाल निश्चित ही भारतीय राजनीति, संसद और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

सुप्रीम कोर्ट बोला – पूरे देश को साफ हवा का हक

-पटाखों पर राष्ट्रीय स्तर पर बैन की ज़रूरत

नई दिल्ली । भारत में प्रदूषण का मुद्दा वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। हर साल खासकर दीपावली के समय दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर प्रशासन और अदालतें सख्त कदम उठाती रही हैं। ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि साफ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए? अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण की कोई भी नीति केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि पूरे भारत में लागू होनी चाहिए।

अदालत की टिप्पणी क्यों अहम है?

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक पटाखों पर सख्त प्रतिबंध मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर में ही लागू किए जाते रहे हैं। यहां की स्थिति खासकर गंभीर मानी जाती है क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण, पराली जलाना और भारी ट्रैफिक पहले ही हवा को जहरीला बना देते हैं। ऐसे में पटाखे हालात को और बिगाड़ देते हैं। लेकिन अदालत ने यह साफ किया कि दिल्ली कोई अलग देश नहीं है। प्रदूषण केवल एक शहर या राज्य की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चुनौती है। अगर एक क्षेत्र में साफ हवा जरूरी है तो दूसरे क्षेत्रों के नागरिक भी उसी अधिकार के हकदार हैं।

पृष्ठभूमि: 3 अप्रैल 2025 का आदेश

दरअसल, 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया था। इस आदेश को कुछ संगठनों और व्यापारियों ने चुनौती दी। उनका कहना था कि यह प्रतिबंध केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित न रहे और अगर इसे लागू करना है तो पूरे देश में लागू किया जाए। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि अदालत केवल दिल्ली के लिए कोई अलग नीति नहीं बना सकती।

साफ हवा का अधिकार – एक मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" का उल्लेख है। इसमें "साफ और स्वस्थ वातावरण" को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक को दूषित हवा में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस अधिकार को और मज़बूत करती है। अदालत ने संकेत दिया है कि हवा से जुड़ी नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी होनी चाहिए।

पटाखों से प्रदूषण क्यों बढ़ता है?

पटाखों के फूटने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई जहरीली गैसें निकलती हैं। यह गैसें वायु प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देती हैं। साथ ही पटाखों से निकलने वाले सूक्ष्म कण (PM 2.5 और PM 10) फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। पटाखों का असर केवल हवा तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी पैदा करता है। इससे बुजुर्गों, बच्चों और पालतू जानवरों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

व्यापारियों और समाज की दलीलें

पटाखों पर प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर छोटे व्यापारियों और कारीगरों पर पड़ता है। पटाखा उद्योग तमिलनाडु के सिवाकासी जैसे इलाकों में लाखों लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग का कहना है कि अचानक लगे प्रतिबंध से उनकी रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाता है। समाज के एक वर्ग का कहना है कि पटाखे भारतीय त्योहारों की परंपरा और खुशियों का हिस्सा हैं। पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय "ग्रीन पटाखों" को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ग्रीन पटाखे क्या हैं?

केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने कुछ साल पहले "ग्रीन पटाखे" विकसित किए थे। इनसे 30% कम प्रदूषण फैलता है और इन पर QR कोड होता है, जिससे असली-नकली पटाखों की पहचान हो सके। लेकिन इनकी उपलब्धता और लोकप्रियता अभी सीमित है।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही साफ हवा के अधिकार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में चुनौतियां होंगी। पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी। साथ ही राज्यों को भी सहयोग करना होगा। लंबे समय में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल पटाखों का प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। उद्योगों, वाहनों और कृषि से जुड़े प्रदूषण पर भी काबू पाना होगा। साथ ही आम लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है कि त्योहार खुशी मनाने का जरिया हैं, न कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का।

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले हिंसा भड़की

-चुराचांदपुर में पोस्टर-बैनर फाड़े और आगजनी

इंफाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से महज़ दो दिन पहले राज्य में फिर से तनाव और हिंसा की आग भड़क उठी। चुराचांदपुर जिले के पीसोनमुन गांव में गुरुवार देर रात उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उन्हें आग के हवाले कर दिया। यह इलाका चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूत्रों के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि, कितने लोग घायल हुए हैं, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और हालात पर नजर रखी जा रही है।

मोदी का कार्यक्रम और सौगात

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे। यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी लगभग 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से वे करीब 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यह इलाका कुकी समुदाय बहुल है। वहीं इंफाल, जो मैतेई समुदाय बहुल इलाका है, वहां से मोदी 1,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्‌घाटन करेंगे। सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट राज्य के विकास को गति देंगे और दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने में मददगार साबित होंगे।

मणिपुर की पृष्ठभूमि

मई 2023 से मणिपुर जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब तक थम नहीं पाया है। इस हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू कर रखा है। हिंसा के कारण राज्य का सामाजिक ताना-बाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है।

दौरे का राजनीतिक और सामाजिक महत्व

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन भर नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी गहरे हैं। यह दौरा हिंसा प्रभावित इलाकों को यह संदेश देने की कोशिश है कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। चुराचांदपुर (कुकी बहुल) और इंफाल (मैतेई बहुल) – दोनों इलाकों में प्रोजेक्ट लॉन्च कर मोदी सरकार यह दिखाना चाहती है कि विकास सभी के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। इसके ज़रिए शांति और स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, दौरे से पहले उपद्रवियों द्वारा पोस्टर-बैनर फाड़ने और आगजनी की घटना यह बताती है कि मणिपुर में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोगों के बीच असंतोष और अविश्वास की खाई अब भी गहरी है।

आगे की चुनौती

मणिपुर में शांति बहाल करना केंद्र और राज्य प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

नेपाल संकट: हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए प्रमुख दावेदार

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में पिछले पांच दिनों से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 तक पहुंच गई है, जिनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है, जो गाज़ियाबाद की रहने वाली बताई जा रही हैं। यह घटनाक्रम न केवल नेपाल की लोकतांत्रिक साख पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है।

हिंसा की पृष्ठभूमि

8 सितंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने अचानक ही बड़ा रूप ले लिया। यह आंदोलन मूल रूप से राजनीतिक अस्थिरता और सरकार की नीतियों के खिलाफ था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें आम जनता का गुस्सा भी जुड़ गया। राजधानी समेत कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं। प्रशासन ने स्थिति को काबू करने के लिए कर्फ्यू और इंटरनेट बंद करने जैसे कदम उठाए, लेकिन हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सके। हर गुजरते दिन के साथ मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। केवल पांचवें दिन ही 17 लोगों की जान गई, जिससे कुल संख्या 51 तक पहुंच गई। हजारों लोग घायल हैं और अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है।

राजनीतिक अस्थिरता का दौर

यह संकट केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी गहरी उथल-पुथल मची हुई है। केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। गुरुवार को राष्ट्रपति कार्यालय में दिनभर चली बैठकों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। शुक्रवार सुबह 9 बजे से फिर बातचीत शुरू हुई है, जिसमें अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम और संसद को भंग करने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है।

सुशीला कार्की पर सहमति की संभावना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर लगभग सहमति बन गई है। कार्की अपने सख्त और ईमानदार छवि के लिए जानी जाती हैं। न्यायपालिका में रहते हुए उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए और राजनीतिक दबाव से हमेशा खुद को दूर रखा। यही वजह है कि मौजूदा हालात में उन्हें एक 'निष्पक्ष' चेहरा माना जा रहा है। लेकिन उनकी दावेदारी पर संवैधानिक पेच फंस गया है। दरअसल, संविधान के अनुसार संसद कायम रहते हुए किसी गैर-सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। सुशीला कार्की इस समय संसद की सदस्य नहीं हैं। इसी वजह से उनके नाम को लेकर चर्चा संसद को भंग करने या न करने पर अटक गई है।

राष्ट्रपति बनाम कार्की का तर्क

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति पौडेल संसद को भंग करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में संसद का अस्तित्व बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर संसद को भंग किया गया, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर, सुशीला कार्की का तर्क है कि जब तक संसद भंग नहीं होगी, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना असंभव है। उनका कहना है कि अगर देश को स्थिर नेतृत्व चाहिए तो संविधान के दायरे में रहते हुए इस बाधा को पहले खत्म करना होगा।

भारत और पड़ोसी देशों की चिंता

नेपाल का संकट भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए भी चिंता का विषय है। भारत-नेपाल के बीच खुले बॉर्डर और घनिष्ठ सांस्कृतिक-आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में नेपाल की अशांति का असर सीधे भारत के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है। खासतौर पर यह तथ्य कि हिंसा में एक भारतीय महिला की मौत हो चुकी है, भारत सरकार को भी सक्रिय होने के लिए मजबूर कर रहा है। भारत ने अब तक संयमित प्रतिक्रिया दी है और नेपाल के नेताओं से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने की अपील की है। हालांकि, काठमांडू में भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर रखे हुए है।

आगे की राह

नेपाल का यह संकट केवल सत्ता परिवर्तन का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक मजबूती की असली परीक्षा है। अगर राजनीतिक दल आपसी सहमति से आगे बढ़ते हैं और निष्पक्ष नेतृत्व को मौका देते हैं, तो हालात को जल्द काबू में लाया जा सकता है। लेकिन अगर संसद भंग करने जैसे विवादित कदमों पर ज्यादा समय गंवाया गया, तो जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है। नेपाल इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ सड़कों पर जनता का गुस्सा है और दूसरी तरफ सत्ता की खींचतान। हिंसा में बढ़ती मौतें और अंतरिम नेतृत्व का न होना हालात को और गंभीर बना रहा है।

इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला: 200 की मौत, 1000 घायल

-नेतन्याहू का बयान– "हमने वही किया जो अमेरिका ने किया"

यरुशलम (एजेंसी)। पिछले 72 घंटों में वेस्ट एशिया (मध्य-पूर्व) का माहौल अचानक बदल गया है। इजराइल ने लगातार हवाई और मिसाइल हमले करते हुए 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। इनमें गाजा (फिलिस्तीन), सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से अधिक के घायल होने की पुष्टि हुई है।

कब और कैसे हुए हमले

ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच किए गए। इजराइली वायुसेना और ड्रोन ने अलग-अलग मोर्चों पर ऑपरेशन चलाए। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकाने निशाना बनाए गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास सैन्य अड्डों और हथियार डिपो पर मिसाइल दागी गईं। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हुई। कतर की राजधानी दोहा में हमास के कथित अधिकारियों को टारगेट किया गया। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ट्यूनीशिया में इजराइल ने दावा किया कि वहां हमास के फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई की गई। इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि ये सारे हमले "आतंकी ढांचे को तबाह करने और भविष्य में होने वाले बड़े हमलों को रोकने के लिए" किए गए।

नेतन्याहू का बयान – "हमने वही किया जो अमेरिका ने किया"

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने दोहा (कतर) में हमास के ठिकानों पर हमले की तुलना अमेरिका द्वारा 9/11 के बाद अफगानिस्तान और इराक में की गई कार्रवाइयों से की।

नेतन्याहू ने कहा: "अमेरिका ने 9/11 के बाद आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की थी। इजराइल भी आज वही कर रहा है। जब हमारी सुरक्षा पर खतरा है, तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए।"

अमेरिका की नाराजगी

दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन हमलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से पूरे वेस्ट एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है और वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है। ट्रम्प ने नेतन्याहू से सीधे बातचीत कर "संयम बरतने" की अपील की।

हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंता करने का अधिकार है, लेकिन उसे पड़ोसी देशों पर इतने बड़े पैमाने पर हमले नहीं करने चाहिए।

मरने वालों और घायलों की संख्या

रिपोर्ट्स के अनुसार – गाजा में 90 से ज्यादा लोग मारे गए। सीरिया में 40 मौतें हुईं। लेबनान में करीब 30 लोगों की जान गई। कतर में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यमन में 20 और ट्यूनीशिया में लगभग 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 200 से ऊपर और घायलों की संख्या 1000 से ज्यादा बताई जा रही है।

अरब देशों की प्रतिक्रिया

इजराइल की इस कार्रवाई पर अरब देशों में भारी गुस्सा है। ईरान ने इसे "युद्ध की नई शुरुआत" बताया है। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। तुर्की ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वह तुरंत हमले बंद करे, वरना हालात गंभीर हो जाएंगे। कतर ने साफ कहा कि उसकी राजधानी पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ये हालात पूरे मध्य-पूर्व को नए युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। यूरोपीय संघ ने कहा कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता तो मानवाधिकार संकट और मानवीय त्रासदी बढ़ सकती है।

इजराइल क्यों कर रहा है ये हमले?

विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल की इन कार्रवाइयों के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं: हमास और हिज़्बुल्लाह की बढ़ती ताकत – इजराइल को डर है कि गाजा और लेबनान से मिसाइल हमले बढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय दबदबा कायम रखना – इजराइल यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी भी खतरे को सीमाओं से बाहर जाकर भी कुचल सकता है। अमेरिका की नीति से प्रेरणा – नेतन्याहू की बयानबाज़ी से साफ है कि वे अमेरिकी 'प्रिवेंटिव स्ट्राइक' नीति को दोहराना चाहते हैं।

नेतन्याहू बोले- फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा

-अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे

तेल अवीव (एजेंसी) । इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि फिलिस्तीनी देश का गठन उनके समय में कभी नहीं होगा। उन्होंने यह बयान वेस्ट बैंक के माले अदुमिम सेटलमेंट में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिया। यह समझौता विवादित ई1 (ईस्ट 1) सेटलमेंट परियोजना को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय रही है। ई1 परियोजना के तहत पूर्वी यरुशलम के पास लगभग 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हजारों नए घर, सड़कें और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8,400 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस अवसर पर कहा, "यह जमीन हमारी है। हम अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे।" उनका यह बयान स्पष्ट रूप से इजराइल के फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर उनकी सख्त नीति को दर्शाता है। ई1 परियोजना को इजराइल की रक्षा मंत्रालय की योजना समिति ने हाल ही में अंतिम मंजूरी दी है। इस परियोजना को पहले 2012 और 2020 में अमेरिका और यूरोपीय देशों के विरोध के कारण रोक दिया गया था। इन वर्षों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने लगातार चेतावनी दी थी कि ई1 सेटलमेंट परियोजना वेस्ट बैंक के भूगोल को बदल सकती है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के एकीकरण को प्रभावित कर सकती है। ई1 को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में लगातार विवाद रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों ने बार-बार कहा है कि यह परियोजना वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांट सकती है। इसके प्रभाव से फिलिस्तीनी क्षेत्र का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा अलग हो जाएगा, जिससे स्थानीय प्रशासन, आवागमन और सामरिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से फिलिस्तीनी राज्य की स्थापनात्मक संभावनाएं और भी कम हो जाएंगी। वेस्ट बैंक में माले अदुमिम सेटलमेंट की स्थिति रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र यरुशलम और पश्चिमी वेस्ट बैंक के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ई1 परियोजना के शुरू होने के बाद यह क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में और सुदृढ़ हो जाएगा। नेतन्याहू ने इसे इजराइल की सुरक्षा और विरासत की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस परियोजना को लेकर फिलिस्तीनी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठन विरोध व्यक्त कर रहे हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि ई1 सेटलमेंट परियोजना उनके भविष्य के राज्य को असंभव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनका मानना है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है और वर्तमान संघर्ष को और बढ़ा सकता है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,